

विपक्ष का मानना है, दो दिन की बहस के बाद भी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मूल सवाल अनुत्तरित ही रहे

प्र. मंत्री मोदी के विस्तृत उत्तर के बाद भी, विपक्ष के अनुसार, यह बात साफ नहीं हुई कि राष्ट्रपति ट्रंप की युद्ध विराम कराने में कुछ भूमिका थी या नहीं

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 30 जुलाई। लोकसभा में दो दिन तक चली लंबी बहस और राज्यसभा में हुई दो दिन की चर्चा के बावजूद, ऑपरेशन सिंदूर, जो नृशंस पहलगाम नरसंहार के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सैन्य प्रतिक्रिया थी, से जुड़े विपक्ष के महत्वपूर्ण सवालों के जवाब नहीं मिल सके। सरकार द्वारा इसे “पाकिस्तान में आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने” की निर्णायक कार्रवाई के रूप में प्रोजेक्ट किया गया, लेकिन अब यह रणनीति संदेहों, कूटनीतिक उलझनों और अस्पष्टता से घिरी हुई नजर आ रही है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लोकसभा में दिए गए विस्तृत एवं लम्बे जवाब के बावजूद, सरकार विपक्ष के मुख्य सवालों से किनारा करती दिखी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की कथित

- विपक्ष के अनुसार, उसे सुरक्षा संबंधी इन प्रश्नों का जवाब नहीं मिला:
- (अ) आतंकवादी पहलगाम में घुसे कैसे? और आतंकवादी हमले के बाद कहाँ गये?
- (ब) क्या सभी आतंकवादी मारे गये या कुछ अभी भी घूम रहे हैं? विपक्ष तीन आतंकवादियों को मार गिराने के सरकारी दावे को स्वीकार नहीं करता।
- (स) हवाई हमले में भारत के कितने लड़ाकू विमान खत्म हुए?
- (द) ट्रंप के तथाकथित हस्तक्षेप के बाद, भारत द्वारा जवाबी हमला रोक देने से भारत को क्या लाभ मिला ,रणनीति की दृष्टि से।

भूमिका पर सरकार से बार-बार सवाल किये, जिन्होंने कम से कम 29 बार यह दावा किया कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष के दौरान संघर्षविराम (सीजफायर) में अहम भूमिका निभाई। लेकिन नई दिल्ली ने न

कभी इसकी पुष्टि की, और न सरकारी स्तर पर इसका खंडन किया। संसद में प्रधानमंत्री मोदी के उत्तर ने इस भ्रम को दूर नहीं किया, सिवाय इसके कि उन्होंने दावा किया कि, “संघर्ष विराम में किसी भी विश्व नेता की भूमिका नहीं थी।”

विपक्ष ने सरकार पर बयानबाजी एवं शब्दजाल के पीछे सच्चाई को छिपाने और जवाबदेही से बचने का आरोप लगाया। मोदी सरकार का यह दावा, कि “किसी वैश्विक शक्ति ने भारत को सैन्य अभियान रोकने का निर्देश नहीं दिया”, ट्रंप के बयानों और अमेरिका सहित, अन्य वैश्विक शक्तियों द्वारा चिंता जताने के तुरंत बाद तनाव में आई कमी से मेल नहीं खाता।

सरकार की सबसे बड़ी आलोचना उस समय हुई, जब पहलगाम आतंकी हमला, जिसे सबसे सीमा-पार द्वारा प्रायोजित माना था तथा जिसमें 26 निदोष पर्यटक मारे गए, पर न तो कोई शोक प्रस्ताव लाया गया, और न ही सरकारी स्तर पर शोक व्यक्त किया गया। संसद में इस पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली।

इसके साथ ही, हमले में शामिल पांच आतंकीयों की पहचान, उनके मूल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अन्नपूर्णा रसोई का अनुबंध निरस्त करने पर रोक

जयपुर, 30 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने डींग जिले के नगर में चल रही अन्नपूर्णा रसोई का अनुबंध तय समय से पहले निरस्त करने वाले राज्य सरकार के गत 16 जून के आदेश की क्रियािन्वति पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही, अदालत ने मामले में निदेशक व प्रमुख विशेष सचिव स्थानीय निकाय,

- हाई कोर्ट ने डींग जिले के नगर की अन्नपूर्णा रसोई के बारे में राज्य सरकार के 16 जून के आदेश पर रोक लगाई।

जिला कलेक्टर भरतपुर, कमिश्नर नगर निगम भरतपुर व कार्यकारी अधिकारी, डींग सहित अन्य से जवाब तलब किया है। जस्टिस अनिल कुमार उपमन ने ये आदेश संकल्प शिक्षा समिति की याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता अभिमन्यु सिंह ने बताया कि याचिकाकर्ता को 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘जमानती अपराध पर बेल क्यों नहीं दी गई’

जयपुर, 30 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानती अपराध होने के बावजूद महिला आरोपियों का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर उन्हें जेल भेजने के मामले में संबंधित न्यायिक न्यायिक मजिस्ट्रेट और एडीजे क्रम-6 महानगर द्वितीय के पीठासीन अधिकारी बालकृष्ण कटारा से दो सप्ताह में स्पष्टीकरण देने को कहा है। इसके साथ ही, अदालत ने दोनों आरोपी महिलाओं को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ ने ये आदेश मौतू पारीक और इंदू वर्मा की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता राजेश

- हाई कोर्ट ने निचली अदालत के दो न्यायिक अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा।

महर्षि ने अदालत को बताया कि मामले में पुलिस ने उन्हें फंसाया है और वे निर्दोष हैं। पुलिस अनुसंधान में दोनों के खिलाफ जिन धाराओं में अपराध प्रमाणित माना गया है, वे धाराएं जमानती प्रकृति की हैं। इसके बावजूद, न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजते समय इसका ध्यान नहीं रखा। वहीं, एडीजे क्रम-6 महानगर द्वितीय के पीठासीन अधिकारी ने भी 24 जून को उनके जमानत प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ पत्रों में कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है और इस (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

धनखड़ के इस्तीफे का रहस्य गहराता ही जा रहा है!

नवीनतम चर्चा के अनुसार, धनखड़ आंध्र के कांग्रेस नेताओं से मिलकर चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में आये, उन्हें एनडीए छोड़ने के लिए प्रेरित करने लगे, जिससे मोदी सरकार अल्पमत में आकर गिर जाए

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 30 जुलाई। हालांकि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दिया, लेकिन सरकार से जुड़े स्रोतों का कहना है कि उन्हें इस्तीफा देने को कहा गया, क्योंकि वे कांग्रेस नेताओं के साथ गुप्तचुप मेलजोल बढ़ा रहे थे और सरकार गिराने की साजिश में लगे थे। स्रोतों के अनुसार, इसके लिए धनखड़ ने कांग्रेस नेताओं की एक बैठक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चन्द्रबाबू नायडू के साथ आयोजित कराने की कोशिश की थी, ताकि वे एनडीए से अलग हो जाएं और संसद में मोदी सरकार अल्पमत में आ जाए। हालांकि कहा जाता है कि नायडू ने

- चंद्रबाबू नायडू ने इस “साजिश” से प्र.मंत्री मोदी को अवगत कराया और धनखड़ से इस्तीफा लेने की प्रक्रिया शुरु हुई।
- यह भी कहा जा रहा है कि धनखड़ चाहते थे कि न्यायाधीश वर्मा के “इम्पीचमेंट” का प्रस्ताव, राज्यसभा में पारित हो, जिससे वे “इम्पीचमेंट” की कार्यवाही के लिए अपनी पसंद के सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व एक वरिष्ठ जुरिस्ट का चयन खुद करते।
- पर, लोकसभा द्वारा 145 सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहले पारित हो गया।

इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और प्रधानमंत्री मोदी को धनखड़ की योजना की जानकारी दे दी। धनखड़ संदेह के घेरे में थे, क्योंकि

उनका विभिन्न राजनीतिक दलों से नाता रहा है। वे 1989 से 1991 तक राजस्थान के झुंझुनूं से जनता दल के सांसद रहे और 1990-91 में संसदीय

कार्य राज्य मंत्री भी रहे। इसके बाद 1991 में उन्होंने राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस जाईन कर ली और अजमेर से लोकसभा चुनाव लड़ा, जिसमें वे हार गए। फिर 1993 से 1998 तक वे किशनगढ़ से कांग्रेस के विधायक रहे। एक वरिष्ठ वकील के रूप में उन्होंने 2003 में भाजपा जाईन की और पार्टी की कानूनी समिति का नेतृत्व किया। 21 जुलाई को राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने धनखड़ से कथित साजिश के प्रयासों पर सवाल किया। धनखड़ ने नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिंजिजू से शिकायत की थी कि संसद भवन से लगे उनके आवास पर आने-जाने वाले लोगों की कड़ी निगरानी की जा रही है और कुछ (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राज्य उपभोक्ता आयोग ने सहारा के प्रोजेक्ट मैनेजर को जेल भेजा

जयपुर, 30 जुलाई। राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग ने टॉक रोड पर बीलवा स्थित सहारा ग्राहम सिटी मामले में दिए गए आदेश की पालना नहीं करने के, अवमानना के 56 मामलों में बुधवार को आरोपी प्रोजेक्ट मैनेजर संजय सक्सेना को 13 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज

- आयोग ने बीलवा स्थित सहारा सिटी के मामले में दिये गये आदेश की पालना नहीं करने के अवमानना के 56 मामलों में यह निर्णय सुनाया।

दिया। आयोग के न्यायिक सदस्य निर्मल सिंह व मुकेश और सदस्य रामनिवास सारस्वत ने यह आदेश भारतीय माहना व अन्य की अवमानना याचिकाओं पर दिया। आयोग के स्थायी गिरफ्तारी वार्ंट (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘नागरिकता का सबूत पेश करने की जिम्मेवारी किसकी है?’

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 30 जुलाई। देश के लोकतंत्र के समर्थन में 93 पूर्व नौकरशाहों ने बिहार में चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इन्टेंसिव रिविजन) की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि यह “भारतीय लोकतंत्र के लिए अब तक का सबसे बड़ा खतरा” है।

पूर्व नौकरशाहों ने एक खुले पत्र में लिखा है कि चुनाव आयोग सिद्धांत और व्यवहार को उलट रहा है, और नागरिकता साबित करने का भार मतदाता पर डाल रहा है, बजाय इसके कि अधिकारी यह प्रमाणित करें कि उन्होंने किसी व्यक्ति को फर्जी नागरिकता के आधार पर क्यों सूची से बाहर रखा है।

पूर्व नौकरशाहों ने चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया को लोकतंत्र पर हमला बताया है, जिससे एक बड़े वर्ग के लोग, खासकर वे, जिनके पास नागरिकता के दस्तावेज नहीं हैं या बहुत कम हैं, अपने मताधिकार से वंचित हो सकते हैं।

चुनाव आयोग ने जिम्मेवारी मतदाता पर डाल दी, जबकि, पहले चुनाव आयोग किसी भी व्यक्ति का मतदान का अधिकार छीनने से पहले कारण बताकर संतुष्ट करता था कि उस व्यक्ति का नाम मत सूची से क्यों काटा जा रहा है

ये सेवानिवृत्त अधिकारी भारत सरकार की तीन अखिल भारतीय सेवाओं और अन्य केन्द्रीय सेवाओं से हैं और संवैधानिक आचरण समूह (कॉन्स्टिट्यूशनल कन्डक्ट ग्रुप) से जुड़े हुए हैं। उन्होंने लिखा, “बिहार में मतदाता सूची के इस “निरर्थक” विशेष पुनरीक्षण को जारी रखना और इसे आगे चल कर देश भर में लागू करना, भारतीय लोकतंत्र के लिए अब तक के सबसे बड़े खतरों में से एक है।”

पत्र में कहा गया है, “हम यह पत्र गहरी चिंता के साथ लिख रहे हैं, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लोकतंत्र की नींव, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, पर सीधा हमला हो रहा है।”

उन्होंने आगे कहा, “यह हमला बेहद चालाकी से किया जा रहा है, जहां

- देश के 93 रिटायर्ड टॉप अफसरों ने खुला पत्र लिखकर चुनाव आयोग के इस निर्णय को प्रजातंत्र के समक्ष अब तक का सबसे बड़ा खतरा बताया।
- पत्र के अनुसार, भारत में आज भी अधिकतर लोगों के पास दस्तावेज नहीं होते, जो यह साबित करें कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक है। कमज़ोर व गरीब वर्ग के लोग तो विशेषकर इन दस्तावेजों से महरूम हैं।
- एक और अहम सवाल है जो इस पत्र में शीर्ष रिटायर्ड अफसरों ने उठाया है, क्या चुनाव आयोग को संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं कि वह किसी की भी नागरिकता किसी भी कारण से रद्द कर सकता है।

मतदाता सूची को शुद्ध करने के नाम पर, मतदाताओं के एक बड़े हिस्से को, खासतौर पर गरीबों और हासिए पर मौजूद लोगों को, जिनके पास

नागरिकता के पर्याप्त दस्तावेज नहीं हैं, वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है।”

पत्र में कहा गया है, “पूर्व में चुनाव

आयोग ने मतदाता सूची तैयार करने के लिये दस्तावेजों की जांच के मामले में उदार और लचीला रवैया अपनाया था, आयोग अच्छी तरह जानता था कि अधिकांश भारतीयों के पास अपनी नागरिकता को सिद्ध करने के लिये पूर्ण दस्तावेज नहीं होते। उस समय यह मान लिया गया था कि विशेष रूप से गरीबों को सरकारी दस्तावेजों की उपलब्धता में बहुत कठिनाई होती है और उन्हें मतदाता सूची में शामिल करने के लिए अतिरिक्त रूप से सक्रिय उपायों की जरूरत होती है। अब यह प्रक्रिया पलट दी गई है, जिससे यह सुनिश्चित हो गया है कि जिनके पास दस्तावेज नहीं हैं, उन्हें मतदाताओं से वंचित कर दिया जाएगा।”

पत्र में यह भी कहा गया है कि चुनाव आयोग ने लंबे समय से चले आ

रहे नियमों को उलट दिया है और अब नागरिकता सिद्ध करने का बोझ मतदाता पर ही डाल दिया गया है।

पत्र में यह भी आरोप लगाया गया कि चुनाव आयोग ने असंवैधानिक रूप से अपने अधिकारियों को किसी का भी नाम मतदाता सूची में जोड़ने या हटाने का अधिकार दे दिया है।

पत्र में कहा गया है, “इस पूरी कवायद का जारी रहना तथा इसके बाद इसका पूरे देश में पहुँचना भारतीय लोकतंत्र के लिए अब तक के सबसे बड़े खतरों में से एक है और यह खतरा उस संस्था द्वारा पैदा किया जा रहा है, जिसका काम सार्वभौमिक मताधिकार व्यवस्था को मजबूत करना है। मतदाता सूची को अपडेट करना तो चुनाव आयोग का नियमित एवं सामान्य (रूटीन) कार्य है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हाई कोर्ट ने जयपुर की दूटी सड़कों का प्रसंज्ञान लिया

जयपुर, 30 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों पर चिंता जताते हुए कहा है कि हम इस बात पर विचार करें कि क्या जयपुर अपनी खूबसूरती और विरासत के लिए जाना जाने वाला गौरवशाली गुलाबी नगर बना रहेगा, या फिर अपनी ही

- सर्वे कर दो सप्ताह में तथ्यात्मक रिपोर्ट व चार सप्ताह में सड़कों की मरम्मत का समयबद्ध प्लान पेश करने को कहा।

बुनियादी ढांचे की कमी से ढहते हुए, एक ढुबते हुए शहर में बदल जाएगा। इसके साथ ही अदालत ने मामले में स्वरेणरा से प्रसंज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव, प्रमुख यूडीएच सचिव, जेडीसी, हेरिटेज और ग्रेटर नियम आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। वहीं, अदालत ने जेडीए और निगम आयुक्तों को निर्देश दिए हैं कि सड़कों (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

हमारी आनंदपूर्ण बहकारियाँ ही हमारी उचीड़क चाबुक बन जाती हैं। –शेक्सपियर

राजस्थान में स्कूल भवनों का ढहना- “आओ फूलों के जनाजे देखो”

आपने हमने जनाजो पर फूल चढ़ाते हुए तो बहुत देखे हैं, मगर खुद फूलों के जनाजे देखे तो दिल दहल गया। सात बच्चे जर्जर स्कूल की क्लास रूम में दब कर मर गये और कोई हल्ला ना हुआ। सन्नाटा पसरा रहा है चारों ओर। उनके लिए ना कोई अगरबत्तियाँ जलाई गईं ना ही कोई जुलूस निकाल गये। वे बच्चे गरीब थे इसलिए सरकार ने उनकी हैसियत देख कर उनकी जान की कीमत दस लाख लगाई गई। शिक्षा मंत्री घूम आये, दोषी को सजा देने का आश्वासन देकर। इतना बड़ा हादसा और कोई इस्तीफा नहीं, कोई दोषी नहीं। संवेदनार्थ मर चुकी हैं, हम स्त्रार्थी हो चले हैं। इतने बड़े हादसे के बाद तो लोगों को सड़कों पर उतरना चाहिये था मगर ये सम्भव नहीं था क्योंकि मृतकों में हमारा कोई नहीं था।

छोटे-छोटे मासूम बच्चों का जब सामूहिक संस्कार हुआ तो मोक्ष धाम की धरती भी कांप गई। अधिकार सरकार स्कूल कांपती स्थिति में है। एक सर्वे में 90% सरकारी कर्मचारियों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। मतलब इन स्कूलों में उनके बच्चे भी नहीं पढ़ रहे जो यहाँ पढ़ा कर सरकारी शिक्षक बने बैठे हैं। सात बच्चों की दर्दनाक मृत्यु से मन बहुत विचलित और असह्य है। राजस्थान में सरकारी स्कूलों की जर्जर इमारतें एक के बाद एक ढह रही हैं, और इन हादसों में मासूम बच्चे और शिक्षक अपनी जान गंवा रहे हैं। अभी तो बरसात ने आधा सफर पूरा किया है मानसून पूरा होते होते क्या होगा सोच कर कंपकंपी छूट रही है। 28 जुलाई 2025 को जैसलमेर के हावूर (पूनमनगर) में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के मुख्य द्वार का पत्थर गिरने से छुट्टी के समय एक मासूम छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई, और एक शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह खंभा पहले से ही जर्जर हालत में था, और इसकी मरम्मत के लिए कई बार शिकायत की गई थी, लेकिन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। यह हादसा स्थानीय सत्ता रूढ़ पाटी के विधायक छोट्टीसिंह भाटी के पैतृक गांव में हुआ है जो सरकार की उदासीनता को और भी शर्मनाक बनाता है। इससे ठीक एक दिन पहले, 27 जुलाई 2025 को जोधपुर जिले में एक सरकारी स्कूल की इमारत का एक हिस्सा ढह गया। सीभाग्य से, उस समय कोई बच्चा या शिक्षक मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। लेकिन यह घटना इस बात का संकेत है कि राजस्थान के स्कूलों की स्थिति कितनी भयावह है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन को स्कूल की जर्जर हालत की जानकारी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। 25 जुलाई 2025 को झालावाड़ के पीपलदोई गांव में सरकारी उच्च प्राथमिक स्कूल की छत गिरने से सात बच्चों की मौत और 28 अन्य के घायल होने की दिल दहला देने वाली घटना ने तो पूरे देश को झकझोर कर रख ही दिया है। यह हादसा सुबह 7:45 बजे हुआ, जब बच्चे प्रार्थना सभा के लिए इकट्ठा हो रहे थे। स्कूल की इमारत 78 साल पुरानी थी, और स्थानीय लोगों ने कई बार उसकी जर्जर हालत की शिकायत की थी। बच्चों ने हादसे से पहले छत से कंकड़ गिरने को सात शिक्षकों को बताई थी, लेकिन शिक्षकों ने इसे नजरअंजब कर बच्चों को डांटकर चुप करा दिया। इस हादसे में मरने वाले आठ बच्चे 8 से 11 साल की उम्र के थे, और दो बच्चे गंभीर रूप से घायल होकर घ्छ में पड़ी हैं। झालावाड़ हादसे के ठीक एक दिन बाद, नागौर जिले के डेगाना क्षेत्र में खरियावास के सरकारी प्राथमिक स्कूल की छत अचानक ढह गई। सीभाग्य से, इस समय कोई बच्चा स्कूल में मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। लेकिन यह घटना इस बात का प्रमाण है कि स्कूल भवनों की जर्जरता पूरे राज्य में एक महामारी की तरह फैल चुकी है। स्थानीय लोगों ने गुस्सा जाहिर करते हुए सवाल उठाया कि अगर बच्चे मौजूद होते, तो तौन जिम्मेदार होता? राज्य के शिक्षामंत्री मदन दिवाकर ने हादसे का नैतिक दायित्व लेते हुए कहा कि सरकार को प्रक्रिया से ही भवनों के मरम्मत का पैसा भेजना जाएगा। इसमें किसी को पैराराज नहीं हो सकता लेकिन हम हादसों का इन्तजार क्यों करते हैं। सरकार को यह सब समय से पहले क्यों नहीं सुझता। राजस्थान में स्कूल भवनों के ढहने की घटनाएं कोई नई बात नहीं है। 2023 में बीकानेर जिले के एक सरकारी स्कूल में छत का एक हिस्सा गिरने से तीन बच्चे घायल हो गए थे। इस घटना के बाद सरकार ने एक जांच कमेटी गठित की थी, लेकिन इसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। स्कूल की मरम्मत के लिए स्वीकृत राशि का उपयोग नहीं हुआ, और भ्रष्टाचार के आरोप लगे। 2022 में उदयपुर के एक सरकारी स्कूल में दीवार गिरने से दो बच्चों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन ने मरम्मत के लिए 50 लाख रुपये की घोषणा की, लेकिन दो साल बाद भी वह स्कूल जर्जर हालत में है। 2021 में जयपुर के एक सरकारी स्कूल में बारिश के कारण छत से पानी रिसने की वजह से दीवार ढह गई थी, जिसमें एक शिक्षक और एक बच्चा घायल हो गए थे। इस घटना के बाद सरकार ने सभी स्कूलों में सुरक्षा ऑडिट का वादा किया था, लेकिन यह केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित रह गया। इन घटनाओं के बाद सरकार ने हर बार जांच कमेटियाँ गठित कीं, मुआवजे की घोषणाएं कीं, और स्कूलों की मरम्मत के लिए बजट आवंटित करने का दावा किया। लेकिन वास्तविकता यह है कि इनमें से अधिकांश वादे हवा-हवाई साबित हुए। 2023 में बीकानेर हादसे के बाद स्वीकृत राशि का केवल 30% ही उपयोग हुआ, और बाकी राशि भ्रष्टाचार और प्रशासनिक देरी की भेंट चढ़ गई। उदयपुर हादसे के बाद घोषित 50 लाख रुपये का उपयोग आज तक नहीं हुआ, और वह स्कूल आज भी बच्चों के लिए खतरा बन रहा है।

इन ताजा हादसों ने राजस्थान सरकार की लापरवाही को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। शिक्षा विभाग की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में 2,710 स्कूल भवनों को बड़े पैमाने पर मरम्मत की आवश्यकता है, और 2,256 स्कूल भवन जर्जर हालत में हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि समस्या व्यापक और गंभीर है, हकीकत में यह आंकड़ा भी कागजी है वास्तविकता इससे अधिक खराब है। फिर भी, सरकार ने समय रहते इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। झालावाड़ हादसे में यह सामने आया कि स्कूल की इमारत को जर्जर भवनों की सूची में शामिल ही नहीं किया गया था। यह न केवल लापरवाही है, बल्कि एक आपराधिक कृत्य है। अगर शिक्षा विभाग को इस स्कूल की स्थिति की जानकारी नहीं थी, तो उनकी सूची कितनी विश्वसनीय है? क्या अन्य स्कूल, जो इस सूची में नहीं हैं, वाकई सुरक्षित हैं? शिक्षा मंत्री मदन दिवाकर ने झालावाड़ हादसे की 'कोरेस का पाप' बनाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना चाहते हैं, अगर पिछले पांच वर्षों में कोरेस की सरकार थी तो उससे पहले भाजपा की सरकार रही थी अत: यह बयान न केवल अनुचित है, बल्कि उस मानसिकता को दर्शाता है जो समस्याओं के समाधान के बजाय राजनैतिक दोषारोपण को प्राथमिकता देती है। क्या सात बच्चों की मौत और जैसलमेर में एक मासूम छात्रा की जान जाने के बाद भी सरकार का 'चरणबद्ध' भवनों की मरम्मत का दृष्टिकोण उचित है? क्या मासूमों की जान को कीमत इतनी सस्ती है कि सरकार भवनों धीरे-धीरे ठीक करने की बात करे? जैसलमेर हादसे में, जहां सरकार के अपने विधायक के अपने गांव में ही हादसा हुआ, सरकार की चुप्पी और भी अखरने वाली है। पिछले साल स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए 82 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, और इस साल यह राशि बढ़ाकर 175 करोड़ रुपये की गई। लेकिन यह राशि भी अर्पण्य है, क्योंकि 2,710 स्कूलों की मरम्मत के लिए 254 करोड़ रुपये की जरूरत है, जो अभी भी वित्त विभाग में मंजूरी के लिए अटक पड़ी है। यह प्रशासनिक देरी और भ्रष्टाचार का एक जीवन्त उदाहरण है, जो बच्चों की जान से खिलवाड़ कर रहा है।

झालावाड़ हादसे के बाद पांच शिक्षकों और एक शिक्षा विभाग के अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। यह कार्रवाई जरूरी थी, क्योंकि बच्चों की शिकायतों को नजरअंजब करना और उन्हें डांटकर चुप कराना शिक्षकों की गैर-जिम्मेदाराना हरकत थी। लेकिन क्या यह हादसा केवल शिक्षकों की गलती का नतीजा था? शिक्षकों ने कई बार स्कूल की जर्जर हालत की शिकायत की थी, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। ग्रामों में ने भी अधिकारियों से मरम्मत की गुहार लगाई थी, लेकिन उनकी बात अनसुनी कर दी गई। शिक्षकों को निलंबित करना एक आसान रास्ता है, जो सरकार को अपनी जवाबदेही से बचने का मौका देता है। शिक्षक न तो इंजीनियर हैं, न ही उनके पास स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए बजट या अधिकार हैं। फिर उन्हें अकेले जिम्मेदार ठहराना कितना उचित है? शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन, और सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) की भूमिका को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? जैसलमेर और जोधपुर हादसों में भी यही पैटर्न देखने को मिला, जहां सरकार ने तुरंत शिक्षकों पर कार्रवाई की, लेकिन असल जिम्मेदारी-प्रशासन और PWD-को छुने की हिम्मत नहीं दिखाई। यह साफ है कि सरकार शिक्षकों को बलि का बकरा बनाकर अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रही है। हां अगर यही हादसा किसी प्राइवेट स्कूल में हो जाता तो पूरा प्रशासनिक अमला स्कूल संचालक के खिलाफ सक्रिय हो जाता और अब तक उसे सलाखों के पीछे धकेल चुका होता और ताबडतोड़ अदालतों और उपदेशों की बाढ़ आ जाती।

राजस्थान में स्कूल भवनों के ढहने की घटनाएं भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अक्षमता का परिणाम हैं। एक जगह शिक्षा कहा गया है कि “जहां निर्माण, वहां भ्रष्टाचार” भारत की कटु सच्चाई है। झालावाड़ हादसे के बाद केंद्र सरकार ने एक बार फिर सभी राज्यों को स्कूलों में सुरक्षा ऑडिट करने का निर्देश दिया, लेकिन यह केवल एक औपचारिकता भर साबित होगी, अगर इसका सख्ती से पालन नहीं किया गया। झालावाड़ हादसे में मृत बच्चों के परिवारों ने 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और एक पुरस्कार को संविदा पर नौकरी देने की घोषणा की गई है। जैसलमेर हादसे में भी सरकार ने मुआवजे की घोषणा की है, लेकिन क्या यह मुआवजा उन मासूमों की जान वापस ला सकता है? एक पिता, छोट्टलाल, ने अपने दोनों बच्चों-कान्हा और मीना-को झालावाड़ हादसे में खो दिया। एक आठ साल का बच्चा, कार्तिक, अपनी चार बहनों का इकलौता भाई था। अब उसकी बहनें किसे राखी बांधेंगी? जैसलमेर में मृत छात्रा के परिवार का दर्द भी कम नहीं है। ये बच्चे गरीब और बहुजन समाज से थे, जो निजी स्कूलों की मोटी फीस नहीं दे सकते। सरकारी स्कूल उनकी एकमात्र उम्मीद थे, लेकिन सरकार ने उनकी इस उम्मीद को भी धोखा दिया। जैसलमेर में यह तथ्य और भी दुःखद है कि हादसा विधायक के अपने गांव में हुआ, फिर भी सरकार और प्रशासन खामोश रहे।

यह समस्या केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है। देश भर में सरकारी स्कूलों की हालत खस्ता है। ओडिशा में 12,343 स्कूल जर्जर हैं, महाराष्ट्र में 8,071, पश्चिम बंगाल में 4,269, गुजरात में 3,857, आंध्र प्रदेश में 2,789, मध्य प्रदेश में 2,659, और उत्तर प्रदेश में 2,238 स्कूल खराब हालत में हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि यह एक राष्ट्रीय संकट है, जिसे नजरअंदाज करना अब असंभव है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झालावाड़ हादसे के बाद एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई और सभी सरकारी भवनों की सुरक्षा समीक्षा के लिए एक कमेटी गठित की। यह कदम सराहनीय है, लेकिन यहां खानापूर्ति होकर न रह जाए? जैसलमेर और जोधपुर, झालावाड़ के हादसों के बाद भी सरकार की ओर से कोई ठोस बयान या कार्रवाई नहीं देखी गई। पहले भी ऐसी कमेटियां बनती रही हैं, और नतीजा शून्य रहा है। इस बीच राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल भवनों की स्थिति पर स्वयं सेंशन लेकर नोटिस जारी किया है उधर केंद्र सरकार ने भी देश भर के स्कूलों में सुरक्षा ऑडिट के निर्देश दिए हैं, जो 2021 के सुरक्षा दिशा-निर्देशों और 2016 के आवाह प्रबंधन निर्देशों के अनुसार होंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन निर्देशों का पालन होगा? क्या स्थानीय प्रशासन और शिक्षा विभाग इस ऑडिट को गंभीरता से लेगे, या यह भी एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा? इस संकट से निपटने के लिए सरकार को तत्काल सुरक्षा ऑडिट करना होगा, जिसमें सभी सरकारी स्कूलों की जांच की जाए और जर्जर भवनों को तुरंत बंद कर बच्चों को वैकल्पिक व्यवस्था में ढ़ाया जाए। मरम्मत के लिए राशि को तुरंत जारी किया जाए, और अर्धक उपयोग में पावर्शिता सुनिश्चित की जाए। इतना ही नहीं भवन मरम्मत के लिए अनापत्ति मिथी का भी प्रथक से प्रावधान हो जिसे जिला कलेक्टर स्वीकृत करने के लिए अधिकृत हों। मरम्मत कार्यों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक स्वतंत्र निगरानी समिति गठित की जाए केवल शिक्षकों को दोषी ठहराने के बजाय जिला प्रशासन, और PWD के अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। स्कूल प्रबंधन समितियों और स्थानीय पंचायतों को भवन सुरक्षा और रखरखाव के लिए प्रशिक्षित किया जाए। जर्जर स्कूलों को ध्वस्त कर उनके स्थान पर आधुनिक और सुरक्षित भवनों का निर्माण किया जाए। स्कूलों में नियमित रूप से आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण और मौक ड्रिल आयोजित किए जाएं।

अगर अब भी सरकार नहीं जागती, तो अगली दीवार कहीं और गिरेगी, और तब शायद सवाल पूछने वाला कोई नहीं बचेगा।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र मोहन शर्मा,
वरिष्ठ साहित्यकार शिक्षाविद् और चिन्तक

गोस्वामी तुलसीदास : एक संत कवि के सामाजिक सरोकार



राजेश्वर सिंह

गोस्वामी तुलसीदास मध्यकालीन भारत की भक्ति काव्य परंपरा की सगुण शाखा के शौर्यश्रेय कवि हैं। उन्होंने श्री रामचरितमानस, कवितावली , दोहावली सहित अनेकानेक ग्रंथों का प्रणयन किया जिसमें मानस की प्रतिष्ठा एक धर्मग्रंथ के रूप में व एक कालजयी साहित्यिक कृति के रूप में आज तक बरकरार है और भविष्य में भी बनी रहेगी।मानस की अघार लोकप्रियता का आधार केवल धार्मिक नहीं है। इसमें व गोस्वामी जी की अन्य कृतियों में न केवल तात्कालिक परिवेश व जनजीवन के दुःख, कष्ट, पीड़ा, व्यथा और वेदना का सजीव चित्रण है वरन इनमें इसको सहन व शमन करने के लिए तमाम उपायों का प्रतिपादन किया गया है, जिनमें राम की भक्ति सर्व प्रमुख है। यह तुलसी के पालन पोषण, अध्ययन, चिंतन तथा समकालीन परिवेश से अर्जित संस्कार से उद्भूत समाधान है। किंतु तुलसी यहीं पर नहीं रुकते। वह अकाल, दुर्मिष्ट, व्याधि व क्षुधाकुलता का वर्णन तो करते ही है पर उसके साथ ही राम राज्य के रूप में एक आदर्श राज्य तथा जनहितकारी शासन तंत्र की संकल्पना भी प्रस्तुत करते हैं जो कि तत्कालीन शासकों पर एक अप्रत्यक्ष प्रहार की श्रेणी में ही रखा जा सकता है।

तुलसी जब कहते हैं कि “जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, ते नृप अवसि नरक अधिकारी” तो उनकी निर्भीकता व स्पष्टवादिता की कल्पना करके दंग रह जाना पड़ता है।

तुलसी जीवन मरण के बंधन से मुक्ति की तलाश में किसी पर्वत की खोह या कंदरा में ध्यान साधना करने वाले संत नहीं थे। वह आम जनता के जीवन के दुःख व कष्ट से जुड़े हुए संत कवि थे। कवितावली में जब वह कहते हैं कि किसान के लिए खेती बाड़ी नहीं है, भिखारी के लिए भोज नहीं है, व्यवसायी के लिए वाणिज्य नहीं है और नौकर के लिए नौकरी नहीं है। जीविकाविहीन लोग एक-दूसरे से चिंतित होकर पुछ रहे हैं कि कहां जाएं और क्या करें, तो बरबस ही आज के हिंदुस्तान का चित्र आंखों के समक्ष समुपस्थित हो जाता है जहाँ स्थितियां पहले से भी ज्यादा विकट और विकराल हो गई हैं।

जैन सामान्य के सुख-दुःख से तुलसी के अभिन्न जुड़ाव का कारण यह था कि उनका स्वयं का बचपन नारकीय अभाव, बुभुषा और भिक्षावृत्ति पर अवलंबित था। इसका साकार वर्णन वह कवितावली में करते हैं जब वे कहते हैं कि मैं धूप से बिलबिलाते हुए एक द्वार से दूसरे द्वार पर भिक्षाटन किया करता था व भिक्षा में मिले हुए अन्न के दानों को ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी चार फल समझता था। गरीबी व अभाव के इस स्वअर्जित व स्वानुभूत अनुभव के कारण ही वह आम जन के दैनिक जीवन की पीड़ा और अभाव को इतनी गहराई से अभिव्यक्त कर पाते थे।

विद्याध्ययन की समाप्ति के उपरांत जब उन्होंने काशी को अपनी कर्म भूमि बनाया तो वहां के पंडितों ने तुलसी को ब्राह्मण मानने से ही इनकार कर दिया। परिणामस्वरूप तुलसी को लेखनी से

इन कालजयी पंक्तियों का प्रणयन हुआ जो कहती हैं कि चाहे तुम लोग मुझे धूर्त कहो या अवधूत, राजपूत कहो या जुलाहा, मुझे किसी की बेटी से बेटा नहीं ब्याहना है और न किसी की जाति बिगाड़नी है। तुलसी तो राम का प्रसिद्ध गुलाम है, जिसे अन्य लोग चाहे जो कहें, वह मांग कर खाता है और मस्जिद में सोता है, उसे किसी से भी कुछ लेना देना नहीं है।

एक तरफ प्रचंड दैन्य और दूसरी तरफ प्रखर आत्मविश्वास, यह तुलसी के व्यक्तित्व और चरित्र की विशेषता है। दीनता आई है, घोर अभावग्रस्त बचपन और जाति आधारित अपमान से और आत्मविश्वास आया है राम की भक्ति से। वह कहते हैं कि हम तो जन्म से ही जहर पीने वाले हैं जो लोगों की व्यंग और कटुक्तियां सुनते और सहते हैं कि आज के हिंदुस्तान में भी श्रमजीवी जातियों व स्त्रियों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति दयनीय ही है। आज भी उन्हें सामाजिक व्यवस्था में समानता पर आधारित सम्मान प्राप्त होना बाकी है। यह सही है कि तुलसी अपने समय, परिवेश, पालन पोषण व संस्कार की आधारित सम्मान प्राप्त होना बाकी है।

यह सही है कि तुलसी अपने समय, परिवेश, पालन पोषण व संस्कार की आधारित सम्मान प्राप्त होना बाकी है। यह सही है कि तुलसी अपने समय, परिवेश, पालन पोषण व संस्कार की आधारित सम्मान प्राप्त होना बाकी है। यह सही है कि तुलसी अपने समय, परिवेश, पालन पोषण व संस्कार की आधारित सम्मान प्राप्त होना बाकी है।

झालावाड़ हादसे के तुरंत बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों के लिये बजट की स्वीकृति दी

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पीपलोद स्कूल हादसे के दिन ही 3688 आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट जारी किया



हिमांशु सिंह

हादसा होना बेहद दुःखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें दोषियों के लिए माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे हादसों से सबक लेकर भविष्य के लिए बेहतर चौकसी और समन्वय ही हादसे में मृत बच्चों को श्रद्धांजलि होगी। झालावाड़ के पीपलोद स्कूल हादसे के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बहुत पीड़ा का अनुभव किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने परिवार के मुखिया का कर्तव्य निभाते हुए शोक की इस घड़ी में त्वरित फैसले लेकर ठोस कदम उठाए हैं जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति न हो।

गत 25 जुलाई को हुए इस हादसे के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला कलेक्टर की बैठक ली, उन्हें सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए और उसी

दिन शाम को साढ़े छह बजे प्रदेश के 3,688 आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट जारी किया। प्रदेश के 1,936 विद्यालयों में मरम्मत, उन्नयन और विकास कार्यों के लिए 160 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए गए हैं।

मेवात, डांग, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम और विधायक कोष से भी मरम्मत के लिए राशि को 15 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया है। हर विधानसभा क्षेत्र में सरकारी कार्यालयों की मरम्मत के लिए 3 करोड़ रुपए मिलेंगे।

यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि सीएम शर्मा के निर्देशन में शासन और प्रशासन ने इस दुर्घटना के बाद बहुत स्विफ्ट रেসपोंस दिया। यह दिखाता है कि संकट में हम सब एक हैं और प्रत्येक संकट, खतरे को चुनौती के रूप में लेकर जीवटता के साथ इसका जवाब देना हम राजस्थानियों के जीस में है। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निभाता है और यहां भजनलाल शर्मा ने दिखाया है कि नेतृत्व अर्थोर्गिटी, आदेश देने से कहीं आगे की भूमिका में है और वह है।

आमजन के साथ तादात्म्य कर उनको आंकांक्षा, चिंता और आशा को शासन की आंकांक्षा, चिंता और आशा का रूप लेकर लक्ष्य को समय पर प्राप्त करे। सभी जिलों से जर्जर आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूलों व अन्य भवनों की सूची 2 घंटे में तैयार होना, तत्काल एस्टीमेट बनाना, इसे अचूक

■ प्रदेश के 1,936 विद्यालयों में मरम्मत, उन्नयन और विकास कार्यों के लिए 160 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए गए

करवाना, वित्त एवं अन्य विभागों से आवश्यक प्रक्रियाओं की पूर्ति कवा कर कई प्रसार की स्वीकृतियां करवाना इसी संकाम और जैन उन्मुखी नेतृत्व का परिणाम है।

गौरतलब है कि अजमेर जिले के 185, अलवर के 6, ब्यावर के 109, बारां के 48, भीलवाड़ा के 232, बीकानेर के 55, बूंदी के 22, चित्तौड़गढ़ के 51, दौसा के 153, डीडवाना-कुचामन के 260, धौलपुर के 5, डूंगरपुर के 16, हनुमानगढ़ के 168, जयपुर के 123, जालौर के 132, झालावाड़ के 118, झुंझुनूं के 289, करौली के 101, खैरथल-तिजारा के 24, कोटा के 37, कोटपुतली-बहरोड़ के 24, नागौर के 186, पाली के 141, राजसमंद के 81, सलूंबर के 198, सवाई माधोपुर के 120, श्रीगंगानगर के 114, सिरोही के 317, ठोंक के 129 व उदयपुर के 344 आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत के लिए बजट जारी किया गया है। ठीक इसी तरह सीएम शर्मा के निर्देशों पर राजस्थान स्कूल शिक्षा



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

परिषद ने राज्य के 1936 विद्यालयों में मरम्मत, उन्नयन और विकास कार्यों के लिए 160 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि से भवन मरम्मत, छत एवं दीवारों का सुदृढ़ीकरण, फर्श और शौचालय सुधार, बिजली एवं जल सुविधाओं का विकास, खेल मैदान का सुधार तथा कक्षाओं का आधुनिकीकरण किया जाएगा।

इसके तहत अजमेर में 47, अलवर में 48, बालोतरा में 44, बांसवाड़ा में 57, बारां में 36, बाड़मेर में 60, ब्यावर में 29, भरतपुर में 35, भीलवाड़ा में 118, बीकानेर में 56, बूंदी में 35, चित्तौड़गढ़ में 42, चूरू में 27, दौसा में 42, डींग में 30, धौलपुर में 59, डीडवाना-कुचामन में 59, डूंगरपुर में 46, गंगानगर में 37, हनुमानगढ़ में 31, जयपुर में 174,

जैसलमेर में 31, जालौर में 50, झालावाड़ में 51, झुंझुनूं में 44, जोधपुर में 72, कोटा में 41, खैरथल-तिजारा में 11, कोटा में 76, कोटपुतली में 28, नागौर में 49, पाली में 62, फलोदी में 19, प्रतापगढ़ में 33, राजसमंद में 33, सलूंबर में 16, सवाई माधोपुर में 39, सीकर में 42, सिरोही में 27, टोंक में 32 व उदयपुर में 68 विद्यालयों की मरम्मत के लिए बजट जारी किया गया है।

दरअसल हम हमेशा इतिहास से सीखते हैं। पूरी मानव सभ्यता का क्रमिक विकास इसी गुण पर टिका हुआ है। कोई भी सिस्टम 100 फीसदी सुरक्षित नहीं होता लेकिन भजनलाल सरकार हमें आश्चस्त करती है कि हम ऐसे हादसों को परास्त कर आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर कल देंगे, उन्हें हमसे बेहतर नागरिक के रूप में विकसित करेंगे। बतौर सजग और जागरूक नागरिक, आओ! हम भी अपने आसपास के वातावरण, भवन, घरों की स्थिति के लिए जागरूक बनें और ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति होने से रोके।

हिमांशु सिंह राजस्थान सरकार में पीआरओ हैं और वर्तमान में झुंझुनूं में कार्यरत हैं।

	मेघ स्वास्थ्य में सुधार होगा। विवाहित मामलों से राहत मिलेगी। अनहोनी को आंशका से बना मन का भय समाप्त होगा। दिन के मध्याह्न पश्चात परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।
	वृष व्यावसायिक आर्थिक मामलों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। अस्त-व्यस्त निवेचनों में सुधार होगा।
	मिथुन घर-परिवार में अतिथियों का आगमन हो सकता है। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यक्तिगत प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।
	कर्क परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग और व्यक्तिगत प्रयासों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।
	वृश्चिक आर्थिक/वित्तीय मामलों दिन के मध्याह्न पूर्व करने का प्रयास करें। मध्याह्न पश्चात अनावश्यक धन खर्च हो सकता है। घर-गृहस्थी के कार्यों के कारण भागड़ा रहेगी।
	मिथुन अपने अति आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। दिन के मध्याह्न पश्चात अष्टम चन्द्र शुभ नहीं है। दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है।
	धनु व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। नौकरोंपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।
	मकर नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है। व्यावसायिक अड़चनें दूर होने लगेंगी।
	कुंभ चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब होने का भय है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। व्यावसायिक परेशानियाँ अभी बनी रहेगी।

फेफड़ों की अत्याधुनिक देखभाल, अब उदयपुर में पहली बार...



बेसिक और एडवांस्ड ब्रोंकोस्कोपी

एवं उदयपुर में सर्वप्रथम
थोरेकोस्कोपी सूट अब PMCH में

अब फेफड़ों से सम्बंधित उपचार के लिए
नहीं जाना पड़ेगा अहमदाबाद

पल्मोनोलॉजिस्ट्स की अनुभवी टीम



डॉ. सी.एस. पुरोहित
चेस्ट एवं टी.बी. रोग विशेषज्ञ



डॉ. सुनील कुमार
चेस्ट एवं टी.बी. रोग विशेषज्ञ

एडवांस्ड
ब्रोंकोस्कोपी एवं
क्रायो प्रोसीजर
~~₹50000~~
निःशुल्क

एडवांस्ड
थोरेकोस्कोपी
~~₹50000~~
निःशुल्क



डॉ. अतुल लुहाडिया

इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजिस्ट एवं
चेस्ट एवं टी.बी. रोग विशेषज्ञ

निःशुल्क
परामर्श व जाँच

निःशुल्क
भर्ती

निःशुल्क चेस्ट CT-Scan
& सीटी गाइडेड लंग्स बायोप्सी

निःशुल्क
X-Ray, 2D Echo

निःशुल्क ब्रोंकोस्कोपी,
ICDT प्रोसीजर

निःशुल्क
स्पाइरोमेट्री, DLCO

उपलब्ध सुविधाएं

बेसिक ब्रोंकोस्कोपी सेवाएं

- ब्रोंकोएल्वियोलर लैवेज (BAL)
- बायोप्सी
- ट्रांसब्रोंकियल नीडल एस्पिरेशन (TBNA)
- ट्रांस ब्रोंकियल लंग बायोप्सी (TBLB)

- इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी की अत्याधुनिक तकनीकें
- स्पेशल नेगेटिव प्रेशर सूट (Negative Pressure Suite)
- 24x7 क्रिटिकल केयर और आईसीयू सुविधा
- एचडी वीडियो ब्रोंकोस्कोप एवं थोरेकोस्कोप उपकरण

थोरेकोस्कोपी सेवाएं

- डायग्नोस्टिक एवं थेरेप्यूटिक
- बायोप्सी • प्ल्यूरोडेसिस
- एड्हीसियोलाइसिस

एडवांस्ड ब्रोंकोस्कोपी द्वारा उपचार

- पीडियाट्रिक ब्रोंकोस्कोपी • ब्रोंकोस्कोपी इन आईसीयू
- रिजिड ब्रोंकोस्कोपी • इलेक्ट्रोकोटर
- ट्रांस ब्रोंकियल लंग क्रायोबायोप्सी (TBLC)
- क्रायो प्रक्रियाएं (क्रायो बायोप्सी, क्रायो एक्सट्रैक्शन)
- एपीसी (Argon Plasma Coagulation)
- ट्यूमर मास डिबल्किंग - वायुमार्ग से बड़ी गांठें हटाना
- फॉरेन बॉडी रिमूवल - श्वास नली में फंसी वस्तु निकालना
- भारी खून बहाव (Massive Hemoptysis) का प्रबंधन
- ग्लू थेरेपी - वायुमार्ग की ब्लीडिंग रोकने हेतु



मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना



राजस्थान स्वास्थ्य योजना



कर्मचारी राज्य बीमा योजना ESIC



जननी सुरक्षा योजना JSY

योजनाओं एवं सभी इश्योरेंस एवं TPA के कैंसलस ईलाज के लिए अधिकृत हॉस्पिटल

अंबेरी पुलिस से पेसिफिक हॉस्पिटल बेदला के लिए आने एवं जाने के लिए मरीजों को निःशुल्क वाहन की सुविधा

*नियम व शर्तें लागू

पंजीकृत मरीज इस सुविधा का लाभ 31 अक्टूबर 2025 तक उठा सकते हैं



पेसिफिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल

भीलों का बेदला, एन.एच.-27, प्रतापपुरा, अम्बेरी, उदयपुर - 313011 (राजस्थान)

फोन : 8690541110, 8239278607

हाड़ौती में भारी बारिश के कारण कई रास्ते बंद, मध्यप्रदेश से संपर्क कटा

बूढ़ादीत थाना क्षेत्र के झाड़ गांव में कच्चा मकान गिरने से बुजुर्ग की मौत, सड़क पर आया मगरमच्छ

कोटा, (निसं)। हाड़ौती संभाग में अति भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। बुधवार सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। कई जगहों पर बोते 40 घंटे से बारिश हो रही है। इसके चलते जलभराव जैसे हालात हो गए हैं। भारी बारिश के कारण कई रास्ते बंद हैं। वहीं मध्यप्रदेश से संपर्क कट गया।

हाड़ौती की बड़ी नदियों के साथ-साथ उनके सहायक नदियों में भी उफान आ गया है। ऐसे में करीब एक दर्जन से ज्यादा नदियां उफान पर हैं। इसके अलावा गांव की खाड़ी (नाले) भी काफी उफान पर है, जिससे हादसे होने की आशंका है। इन नालों ने कई रास्तों को बंद कर दिया है। इनके तेज बहाव में पुलिया भी टूटकर बह गई, जिन्हें मिलकर हाड़ौती में 50 से ज्यादा रास्ते बंद हैं। बूंदी में लाखेरी के नजदीक कोटा-दीसा-लालसोट मेगा हाईवे पर मेज नदी की पुलिया पर खतरा बना हुआ है। पुलिया को फिलहाल बंद कर दिया है। इस रूट के ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है। हाड़ौती में कालीसिंध, परवन, पार्वती, चंबल, अरू, पाटली, नांगली, ताकली, उजाड़, सुखनी, छापी, अंधेरी, रेणुका, कूल, बाणगांग, चंबली, आहू व मेज नदी सहित अन्य सहायक नदियां भी उफान पर हैं। साथ ही नाहरगढ़ एरिया पहले से ही मध्यप्रदेश से आ रहे पानी के चलते



सड़क पर आए मगरमच्छ को रेस्क्यू कर चंबल नदी में छोड़ा।

डूब में तब्दील हो रहा है। बारां जिले के छबड़ा की टॉवर कॉलोनी में भी पानी प्रवेश कर गया। बारां जिले के छबड़ा में भारी बारिश के चलते गूल में किले की दीवार के पत्थर ढह गए। इसी तरह से केलवाड़ा के जैसवा के गांव में एक घर की छत गिर गई, हालांकि घर में सो रहे पांच सदस्य तुरंत बाहर चले गए थे। इसके अलावा कोटा के खातोली इलाके में भी बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। खातोली कस्बे में बाढ़ जैसे हालात में प्रशासन ने निचली बस्तियों को खाली करना शुरू कर दिया है। लगातार पार्वती नदी में पानी की आवक हो रही है। साथ ही प्रशासन मुनादी भी कर रहा है।

थानाधिकारी मंशीराम बिश्नोई ने

बताया कि लगातार पानी की आवक होने से एहतियात बरत रहे हैं। एसडीएम तहसीलदार अरुण सिंह सहित प्रशासन ग्रामीणों को सरकारी भवनों में शिफ्ट करवा रहे हैं और सतर्कता बरतने के लिए कह रहे हैं। पीपल्स क्षेत्र में मदनपुरा, गोवर्धनपुरा, संग्रामपुरा, रघुनाथपुरा, डोली, नारायणपुरा, किरपुरिया, ख्यावदा, कर्जलिया सहित कई गांव टापू बन गए हैं।

कोटा के बूढ़ादीत थाना क्षेत्र के झाड़ गांव में एक कच्चे घर की दीवार ढहने से 79 वर्षीय खेमराज मौणा की मौत हो गई है। जबकि उनका मूकबधिर बेटा धनराज मलबा गिरने से घायल हो गया। सुल्तानपुर पंचायत समिति के सारोला पंचायत का कचनावाड़ा गांव

में बुजुर्ग की मौत हो गई थी। शमशान में टीनशेड नहीं था ऐसे में तिरपाल की मदद से अंतिम संस्कार किया गया। चंबल नदी की झरेल की पुलिया पर पानी 22 जून से ही यह रास्ता बंद है। जिसे सवा महीने के आसपास हो गया है। इससे कोटा जिले के खातोली एरिया का सीधा संपर्क सवाई माधोपुर से टूटा हुआ है। वर्तमान में चंबल नदी की इस पुलिया पर पानी है। यहां पर स्थित झरेल के बालाजी का मंदिर भी पूरी तरह से जलमग्न है। मध्यप्रदेश सरकार ने खातोली के नजदीक पार्वती नदी पर पुल बनाया था। यह

सबमर्सिबल पुल था जो इस बार बारिश में डूब गया है। इससे पहले राजस्थान सरकार का बनाया पुल भी अक्सर डूब जाया करता था। इस बार नया बना हुआ पुल जिस पर से इस साल ही ट्रैफिक शुरू हुआ था वह भी डूब गया है। इसके चलते मध्यप्रदेश का खातोली से संपर्क टूट गया है। कोटा जिले के अयाना के नजदीक पार्वती नदी की सुरताक क्वांजापुर की पुलिया पर पानी आ जाने के चलते कोटा का मध्यप्रदेश के बड़ौदा श्योपुर से संपर्क कट गया है। यह सड़क मार्ग का सबसे ज्यादा उपयोग बारां जिले के लोग मध्यप्रदेश के श्योपुर जाने के लिए करते हैं।

बूंदी जिले के लाखेरी के नजदीक मेज नदी की पापड़ी पुलिया के क्षतिग्रस्त होने की संभावना बनी हुई है। इसे देखने

■ **कोटा के खातोली इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं, प्रशासन ने निचली बस्तियों को खाली कराना शुरू किया**

के लिए पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे। इसके बाद इस पुलिया पर से आवागमन फिलहाल रोक दिया गया है। बारां जिले में 14 रास्ते बंद हैं। कोटा जिले में सुकेत से जुल्मी रोड, देवली मांझी से ढोटी, नौनेरा से नारायणपुरा, गैता से कीरपुरा, चेचट से चंद्रपुरा रोड भी बंद है।

■ **सड़क पर आया मगरमच्छ:-** शहर के बजरंग नगर में नहर के नजदीक एच 9 फीट लंबा मगरमच्छ देर रात को पहुंच गया था। वन विभाग को भी इसकी सूचना मिली थी जिसके बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया। फॉरेस्ट विभाग के वॉरेंट सिंह हाड़ा ने बताया कि वह मंगलवार देर रात करीब 1 बजे पहुंच गए थे। लेकिन भारी बारिश हो रही थी। इसके चलते रेस्क्यू करने में काफी समय लगा। इसके बाद उसे पौने तीन बजे रेस्क्यू किया गया। इसे ले जाकर वॉटर फिल्टर प्लांट शिवपुरा के नजदीक चंबल नदी में छोड़ा है। यह मगरमच्छ 9 फीट लंबा और करीब 100 किलो वजनी था।

सवाई माधोपुर में बाढ़ के हालात



एसडीआरएफ की दो अलग-अलग टीमों ने चम्बल नदी और लटिया नाले में फंसे नागरिकों को रेस्क्यू किया।

सवाई माधोपुर, (निसं)। जिले में लगातार हो रही मूसलधार वर्षा और जल स्रोतों के उफान के बीच बुधवार प्रातः एसडीआरएफ कमांडेंट राजेन्द्र सिंह मिसौलिया के निदेशन में एसडीआरएफ की दो अलग-अलग टीमों ने चम्बल नदी और लटिया नाले में फंसे 16 नागरिकों को सुरक्षित रेस्क्यू कर जान बचाई।

प्रातः 5:10 बजे पुलिस कंट्रोल रूम से मिली सूचना के आधार पर भरतपुर की सी कम्पनी खण्डार थाना क्षेत्र में तैनात टीम सी-7 को मईकलां गांव में चम्बल नदी के तेज बहाव में फंसे ग्रामीणों के रेस्क्यू के लिए रवाना किया गया। वहीं हैडकॉस्टेबल अशोक कुमार के नेतृत्व में 10 जवानों की टीम आपदा राहत उपकरणों एवं मोटर बोट के साथ मौके पर पहुंची। क्षेत्र में कोटा बैराज के गेट खोलने के कारण नदी उफान पर थी और गांव में पानी भर गया था। रेस्क्यू टीम ने त्वरित कार्रवाई करते

■ **चम्बल नदी व लटिया नाले में फंसे 16 लोगों को बचाया**

■ **ग्रामीणों के साथ 40 मवेशियों को लटिया नदी में सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया**

हुए 3 पुरुष, 2 महिलाएं और 4 बच्चों सहित कुल 9 नागरिकों को लाइफ जैकेट पहनाकर सुरक्षित निकाला और नाव से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इसके साथ ही ग्रामीणों के 40 मवेशियों को भी बहाव से सुरक्षित बाहर लाया गया। इसी प्रकार दूसरी और सवाई माधोपुर शहर के समीप लटिया नाले के तेज बहाव में फंसे 7 नागरिकों को भी एसडीआरएफ की सी-08 टीम ने प्रातः पांच बजे सूचना मिलने के बाद प्रातः 5:50 बजे तक पहुंचकर

सफलतापूर्वक बचाया। यह टीम रिजर्व पुलिस लाइन सवाई माधोपुर में तैनात थी और इसका नेतृत्व हैडकॉस्टेबल धारा सिंह कर रहे थे। लटिया नाले का मिर्जा मोहल्ला और अंसारी मोहल्ला क्षेत्रों में 3 से 4 फीट पानी भर चुका था, जिससे कुछ खाना जलमग्न हो गए। रेस्क्यू टीम ने रफिसयॉ एल, जसपुर के मदद से बाइग्रस्त मकानों तक पहुंच बनाई और सभी नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला। दूसरी ओर मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीना ने बाइग्रस्त क्षेत्रों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और स्थानीय निवासियों से संवाद कर उन्हें हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने लटिया नाले के उफान से शहर के रैगर मोहल्ला, मिर्जा मोहल्ला, अंसारी मोहल्ला, प्रजापत मोहल्ला, खटीक मोहल्ला व अन्य कॉलोनियों में हुई जलभराव की गंभीर स्थिति पर चिंता जताई।

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड	
ई-निविदा सूचना	
दिनांक :- 30/07/2025	
निविदा संख्या एवं दिनांक	कार्य का विवरण
F-9(141)/CC/2022-2025-13	कनका मालपुरा सिन्हाट्ट मांस गांव-मालपुरा तहसील-जयल नागौर में एक 11 / .43 की म्यूटल ग्राउंडिंग रेजिस्टर (एनजीआर) की आपूर्ति, स्वामता, कमीशनिंग और परीक्षण (निविदा दस्तावेजों में उल्लिखित कार्य)। अनुमानित मूल्य (₹) 10.40 लाख, घरेलू राशि (₹) - 20,800 /-, निविदा राशि- 1180 /- अहस्तांतरणीय जी.एस्.टी. सहित। ई-निविदा प्रक्रिया शुरू करने के लिए 500/- का डी.डी. जो कि एन.डी., आर.आर.एस.एल., जसपुर के नाम देय हो।
Dated 25.07.2025 UBN No. MML2526GLOBO00071	उपरोक्त निविदा की विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.rsmm.com अथवा www.sppp.raajasthan.gov.in अथवा प्रबंधक (सांख्यिक-अनुकूल) से उपरोक्त पते पर सम्पर्क करें।
राज.सं.अ.सं./सी/25/7178	

भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर	
क्रमांक :- सेवा./भ.वि./2025-26/10881	
दिनांक :- 28/07/2025	
ऑनलाइन निविदा सूचना सं. 11/2025-26	
राजस्थान के राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु भरतपुर विकास प्राधिकरण में उपयुक्त श्रेणी एवं विभिन्न विभागों में ए तथा एच श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ईप्रोक्वोरमेंट प्रक्रिया से कुल 04 कार्यों हेतु ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।	
उक्त कार्यों का विस्तृत विवरण, निविदा शर्तें, अनुमानित लागत राशि, निविदा बेचने, प्राप्त करने एवं खोलने की दिनांक आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट http://eproc.raajasthan.gov.in , http://www.urban.raajasthan.gov.in/uitbharatpur एवं http://sppp.raj.nic.in portal पर देखा जा सकता है।	
निविदा से संबंधित किसी भी प्रश्न का संशोधन http://eproc.raajasthan.gov.in एवं http://sppp.raj.nic.in portal का अवकाश कर सकते हैं।	
UBN विवरण :- 01 WAQ2526WSO800166, 02. WAQ2526WSO800167, 03. WAQ2526WSRC00168, 04. WAQ2526WSO800169	
राज.सं.अ.सं./सी/25/7188	

कार्यालय नगर पालिका मण्डल केशवराय पाटन जिला - बून्दी (राज0)

npallika3@gmail.com ph.no. 07438-264346

क्रमांक :- न0पा0क0म0/निर्माण/2025-26/1305-1307

दिनांक :-25.07.2025

ई-निविदा सूचना संख्या 02/2025-26

नगर पालिका कंपाउण्ड द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु नगर पालिका कंपाउण्ड में पंजीकृत कार्यों के अनुसार सहायक एवं परीक्षण (निविदा दस्तावेजों में पंजीकृत AA.A श्रेणी के संवेदकों से दी लिकाका पद्धति /ई-निविदा पद्धति से ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्य की निविदा बेचे जाने की दिनांक 25.07.2025 से दिनांक 08.08.2025 प्रातः 9.00 बजे तक है। निविदा शर्तें आदि सम्पूर्ण विवरण <http://sppp.raj.nic.in>, <http://eproc.raajasthan.gov.in> पर देखी जा सकती है।

Sr.No.	UBN No.	Sr.No.	UBN No.
1	DLB2526WSOB12628	2	DLB2526WSOB12629
3	DLB2526WSOB12630	4	DLB2526WSOB12631
5	DLB2526WSOB12633	TENDOR COST - 24.65 LACS	
राज.सं.वा.वा./सी/25/7044		अध्यक्ष	
		अधिशारी अधिकारी	

अवैध बजरी भरे तीन डम्पर जब्त, चालक गिरफ्तार

माण्डलगढ़, (निसं)। मांडलगढ़ के बोगोद थाना क्षेत्र में भीलवाड़ा पुलिस की स्पेशल टीम (डीएसटी) ने बजरी माफिया पर बड़ी कार्रवाई की है। बनाव नदी की ओवरलॉड अवैध बजरी परिवहन करते तीन डम्पर्स को जब्त किया है। पुलिस ने डम्पर चालकों को जमानत पर गिरफ्तार कर लिया है। खनिज विभाग ने डम्पर चालकों के खिलाफ बोगोद थाने में मामला दर्ज कराया है। भीलवाड़ा की स्पेशल टीम ने बुधवार को जोजना-धाकड़खेड़ी सड़क मार्ग पर जा रहे अवैध बजरी भरे ओवरलॉड तीन डम्पर्स को जब्त किया और वाहनों को बीगोद थाने लाकर खड़ा कराया। पुलिस जांच के दौरान तीनों डम्पर के पास बजरी ओरिवहन के वैध दस्तावेज नहीं मिले।

डम्पर चालकों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि बनाव नदी किनारे खटवाड़ा गांव के पास बजरी स्टॉक से जेसीबी से तीनों डम्पर में बजरी भरी गई और मध्यप्रदेश में सप्लाई के लिए ले जाई जा रही थी। सूचना पर खनिज विभाग के फोरमैन ने बोगोद थाने पहुंच कर तीनों अवैध बजरी के डम्पर के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस ने डम्पर चालकों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। खनिज विभाग के मुताबिक पुलिस कार्रवाई के साथ अवैध बजरी खनन और परिवहन करने पर जब्त डम्पर्स से 15 लाख 72 हजार राशि जुर्माना के रूप में वसूली जाएगी। वहीं परिवहन विभाग द्वारा ओवरलॉड की अलग से कार्रवाई की जाएगी और स्टॉक संचालक व जेसीबी को भी जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

अधेड़ से मारपीट की

भीलवाड़ा, (निसं)। रायपुर में खेत में पशु प्रवेश करवाने की रिपोर्ट दर्ज करवाने जान अधेड़ को उस वक्त भारी पड़ गया, जब थाने के सिपाही दशरथ सिंह ने मारपीट कर दी, जिसके कारण अधेड़ का कान का पर्दा भी फट गया, जिसके बाद घायल अधेड़ को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती करवाया है। वहीं परिजनों ने एसपी से आपापी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग की है। घायल के परिजन जगदीश

तेली ने कहा कि कोशियल में रहने वाले मेरे साढ़ू नंद लाल तेली के खेत में शंकर लाल तेली अपने मवेशी चरने के लिए छोड़ देता है, जिसकी उलाहना देने पर शंकर लाल ने नंद लाल से मारपीट की और जब वह इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाने रायपुर थाने में गत तो वहां बोट प्रभारी दशरथ सिंह ने शंकरलाल से सांठ-गांठ करते हुए हमारी रिपोर्ट लेने से इंकार कर दिया और 15 हजार रूपए की मांग रखी।

तेली ने कहा कि कोशियल में रहने वाले मेरे साढ़ू नंद लाल तेली के खेत में शंकर लाल तेली अपने मवेशी चरने के लिए छोड़ देता है, जिसकी उलाहना देने पर शंकर लाल ने नंद लाल से मारपीट की और जब वह इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाने रायपुर थाने में गत तो वहां बोट प्रभारी दशरथ सिंह ने शंकरलाल से सांठ-गांठ करते हुए हमारी रिपोर्ट लेने से इंकार कर दिया और 15 हजार रूपए की मांग रखी।

मालाखेड़ा, सिलीसेढ़ व सरिस्का क्षेत्र में बारिश, खेतों में पानी भरा

■ **सिलीसेढ़ बांध में पानी की आवक बढ़ने लगी**

ने दो दिन तक जिले में स्कूलों का अवकाश घोषित किया है। अलर्ट से पहली रात को जिले के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई थी। वहीं जिले के अन्य ग्रामीण हिस्सों में बुधवार तड़के करीब तीन बजे से सुबह आठ बजे तक लगातार पांच घंटे अच्छी बारिश हुई। इससे खेतों में पानी भर गया और किसानों के चेहरे खिल उठे। ग्रामीणों

का कहना है कि इस बारिश से भूजल स्तर में सुधार आने की उम्मीद है। सबसे अधिक गोविंदगढ़ में 45, थानागाजी में 11, लक्ष्मणगढ़ में 22 और बाकी जगहों पर 2 से 11 मिमी बारिश हुई है। सिलीसेढ़ बांध में अब 26.3 फीट पानी है, जबकि 28.9 फीट के बाद ऊपरा चल सकेगी। जबकि अलर्ट से पहली रात को अलवर में 22, जयसमंद में 30, सोडावास में 24, सिलीसेढ़ में 21, राजगढ़ में 21 सहित अन्य जगहों पर भी हल्की बारिश हुई थी।

डिग्गी में दो युवक डूबे, तलाश जारी

जैसलमेर, (नि.सं.)। जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ तहसील के रणथा गांव में बुधवार दोपहर में युवक पानी की डिग्गी में डूब गए। ग्रामीणों की मदद से व जेसीबी से युवकों की तलाश की जा रही है, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लगा पाया है।

आसपास के लोगों ने उनको पानी में तैरते हुए देखा था। कुछ देर बाद जब वो नजर नहीं आए तो उनकी तलाश करने पर डिग्गी के बाहर जूते चप्पल नजर आए। हादसा फतेहसिंह नामक किसान के खेत में हुआ। युवकों के पानी में डूबने की आशंका के चलते लोगों में सनसनी फैल गई, मगर डिग्गी गहरी होने के कारण वे पानी में नहीं उतर सके। घटना की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण व हिमंझियावाली थाना पुलिस मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से व जेसीबी की मदद से युवकों की तलाश की जा रही है।

सरिस्का टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बढ़ते अवैध कब्जों पर कार्रवाई होगी

■ **केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी साफ कर दिया है कि अतिक्रमण पर अग्रिम कार्रवाई राजस्व और यूआईटी करनी होगी**

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरिस्का बफर में क्षेत्र में बने हुए होटल राजस्व और यूआईटी के क्षेत्र में हैं। जिला प्रशासन की ओर से किए गए सर्वे की रिपोर्ट के बाद उन्हीं विभागों को अग्रिम कार्रवाई करनी है। किसी भी प्रकार का काम, जो अवैध हो और जो बाघों के संरक्षण के लिए हानिकारक होगा, उसे होने नहीं दिया जाएगा। इससे साफ हो गया है कि अब प्रशासन को कार्रवाई

आगे बढ़ानी होगी। प्रशासन की ओर से कुछ माह पहले कराए गए सर्वे में पाया गया था कि सिलीसेढ़ में 14 होटल बफर राजस्व एरिया में बने हुए हैं। इसके अलावा अन्य प्रतिष्ठान भी बफर एरिया में बने हुए हैं, जिन्हें सर्वे में छोड़ दिया गया। अब वे भी सर्वे के दायरे में आएंगे। इसके अलावा टहला एरिया में क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट से एक किलोमीटर के दायरे में 34 होटल आ रहे हैं। अजबगढ़ एरिया में भी 18 होटल व रिपोर्ट हैं। इन सभी को किसी न किसी प्रकार से नोटिस तो जारी हुए, लेकिन उसके बाद प्रशासन ने इन सब मामलों को दबा दिया, लेकिन अब सरिस्का के संरक्षण की बात सामने आ रही है। पूर्व में भी सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण पर कार्रवाई के आदेश किए थे और अब भी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ऐसे में प्रशासन को अब आगे आना होगा।

बारिश और अंधड़ से 100 साल पुराना पेड़ गिरा, कई वाहन क्षतिग्रस्त

भीलवाड़ा, (निसं)। शहर के मंगला चौक में बारिश और अंधड़ के चलते 100 साल पुराना पेड़ गिरने से कार और ऑटो क्षतिग्रस्त हो गये और बिजली के तार टूट गए। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई।

जानकारों के अनुसार पुराने शहर भीलवाड़ा ने करीब 100 वर्षों पुराना पेड़ बारिश के बीच अचानक गिर गया। पेड़ के नीचे दबने से एक कार और ऑटो

क्षतिग्रस्त हो गये, जबकि कई विद्युत पोल और तार टूटने से क्षेत्र को बिजली गूल हो गई। सूचना पर निगम की टीम मौके पर पहुंची और रोड क्लियर करवाया। हादसे की सूचना पर मौके पर बड़ी संख्या में भीड़ भी जमा हो गई।

निगम और सिस्कोर कंपनी की टीम ने पेड़ की कटाई कर उसे हटाने के ईंतजाम किए। पेड़ की टहनियों से एक मंदिर का दरवाजा और सीढ़ियों को भी नुकसान पहुंचा। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।

राजस्थान सरकार						
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, कोटा						
नौलामी सूचना प्रकाशन 05/2025-26						
दिनांक-21.07.2025						
क्रमांक-ख3/कोटा/अना./नौलामी/2025/684						
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय खनि अभियन्ता कोटा क्षेत्राधिकार में विभिन्न राजस्व ग्रामों के खातेदारी/सरकारी खसरों में अवैध खनन/निर्माण चैकिंग के दौरान आरएमएसओर 2017 के नियम 54 व 60 के तहत जम्हाई करने वाली/बनास/मेसन्सरी स्टोन जैसी भी जिले की जहां भी है, उसी स्थिति में नौलामी हेतु देर सीलबन्द लिफाफे में मांगित की जाती है। निम्नलिखित विवरण निम्न तालिका व विभागों वेबसाइट www.mines.raajasthan.gov.in एवं पोर्टल http://sppp.raajasthan.gov.in तथा कार्यालय नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है। उक्त नौलामी में भाग लेने हेतु नौलामी प्रपत्र राशि रुपये 100 का डी.डी./ बैंकर्स चेक निम्न अभियन्ता के नाम जमा करवाकर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय खनि अभियन्ता, खनिज भवन, प्लॉट नं. 3, टैगोर नगर, रावतभाटा रोड, कोटा से प्राप्त किये जा सकते हैं।						
नौलामी हेतु खनिज काली बजरी का संक्षिप्त विवरण						
क्र.सं.	राजस्थान एवं खसरा संख्या तहसील (जहाँ जम्हाई काली बजरी पड़ी है)	खनिज की अनुमानित मात्रा (टनों में)	बयाना/अमानत राशि (₹.में)	निकिदा आमंत्रण तिथि	निकिदा खोलने की तिथि	न्यूनतम बोली राशि (₹.में)/ प्रति टन
1	खसरा 643 किस्म खातेदारी ग्राम खेडीयामान तहसील इन्द्रगढ़ जिला बुंदी	80 टन	3600	04.08.2025	05.08.2025	450
2	खसरा 364 किस्म खातेदारी ग्राम खेडीयादुर्जन तहसील इन्द्रगढ़ जिला बुंदी	300 टन	13500	04.08.2025	05.08.2025	450
3	खसरा 757 किस्म बरानी खातेदारी ग्राम झालौजी का बराना तहसील के. पाटन जिला बुंदी	300 टन	13500	04.08.2025	05.08.2025	450
4	ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा	30 टन	1350	05.08.2025	06.08.2025	450
5	खसरा सं. 1408/516 खातोली से सवाईमाधोपुर रोड ग्राम लाखनी जिला कोटा	30 टन	1350	05.08.2025	06.08.2025	450
6	खसरा सं. 01 ग्राम खातोली जिला कोटा	150 टन	6750	05.08.2025	06.08.2025	450
7	खसरा सं. 525 ग्राम खातोली जिला कोटा	100 टन	4500	05.08.2025	06.08.2025	450
8	खसरा सं. 03 ग्राम खातोली जिला कोटा	100 टन	4500	05.08.2025	06.08.2025	450
9	खसरा सं. 1342/57 खातोली से सवाईमाधोपुर रोड ग्राम खातोली जिला कोटा	80 टन	3600	05.08.2025	06.08.2025	450
10	खातोली इटावा रोड आवासीय कॉलोनी ग्राम खातोली इटावा जिला कोटा	870 टन	39150	05.08.2025	06.08.2025	450
11	खसरा संख्या 845 ग्राम गैता तहसील पीपल्स जिला कोटा	400 टन	18000	05.08.2025	06.08.2025	450
12	ग्राम राजपुरा बबूलिया मुख्य सड़क की ओर	400 टन	18000	05.08.2025	06.08.2025	450
13	ग्राम राजपुरा तहसील पीपल्स जिला कोटा	500 टन	22500	05.08.2025	06.08.2025	450
14	ग्राम हवा खेरौली तहसील पीपल्स जिला कोटा (हवा खेरौली मुख्य सड़क किनारे)	300 टन	13500	05.08.2025	06.08.2025	450
15	ग्राम फतेहपुरखुर्ख तहसील तहसील दीगोद (सरपंच के घर के परिसर में)	20 टन	900	06.08.2025	07.08.2025	450
16	ग्राम मण्डावरा तहसील दीगोद जिला कोटा	80 टन	3600	06.08.2025	07.08.2025	450
17	ग्राम फतेहपुरखुर्ख तहसील तहसील दीगोद	150 टन	6750	06.08.2025	07.08.2025	450
18	ग्राम झोटौली (सुल्तानपुरा मण्डावरा रोड के किनारे)	540 टन	24300	06.08.2025	07.08.2025	450
19	ग्राम झोटौली (सुल्तानपुरा मण्डावरा रोड के किनारे)	151 टन	6950	06.08.2025	07.08.2025	450
20	ग्राम आमोरा ग्राम पंचायत बमोरी तहसील दीगोद (सरपंच निवासी आमोरा के मकान के सामने)	210 टन	9450	06.08.2025	07.08.2025	450
नौलामी हेतु बनास बजरी का संक्षिप्त विवरण-						
1	ग्राम केशोपुरा तहसील पीपल्स जिला कोटा	2016 टन	141120	07.08.2025	08.08.2025	700
2	पुलिस थाना महावीर नगर, जिला कोटा	68 टन	4760	07.08.2025	08.08.2025	700
3	पुलिस थाना उधोग नगर, जिला कोटा	135 टन	9450	07.08.2025	08.08.2025	700
4	पुलिस थाना अयाना जिला कोटा	360 टन	10150	07.08.2025	08.08.2025	700
5	पुलिस थाना भीमगंजमण्डी जिला कोटा स्थान उम्मेद सिंह स्टोडियम	145 टन	10150	07.08.2025	08.08.2025	700
6	पुलिस थाना बोरखेड़ा, जिला कोटा	99 टन	6930	07.08.2025	08.08.2025	700
7	पुलिस थाना रेवेले कॉलोनी, जिला कोटा	160 टन	11200	07.08.2025	08.08.2025	700
8	कार्यालय परिसर खनिज भवन, टैगोर नगर, प्लॉट नम्बर 3, रावतभाटा रोड, कोटा	90 टन	6300	07.08.2025	08.08.2025	700
नौलामी हेतु मेसन्सरी स्टोन का संक्षिप्त विवरण						
1	खसरा संख्या 735 ग्राम दीपपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा	1250 टन	43750	07.08.2025	08.08.2025	350
समूह में देर जम्हाई करने वाली/बनास बजरी/मेसन्सरी स्टोन की प्रत्येक समूह के लिए अलग-अलग बोली देर सीलबन्द लिफाफे में निविदा आमंत्रण तिथि को प्राप्त 11 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यालय खनि अभियन्ता खनिज भवन, प्लॉट नं. 3, टैगोर नगर, रावतभाटा रोड, कोटा के कमरा नम्बर 112 में प्राप्त की जायेगी। निष्पात समग्र तब प्राप्त सीलबन्द निविदा को कटौती द्वारा निविदा खोलने की तिथि को प्राप्त 11 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खनि अभियन्ता कोटा कक्ष संख्या 114 में खोली जायेगी। नौलामी की शर्तें कार्यालय खनि अभियन्ता कोटा व विभागों वेबसाइट www.mines.raajasthan.gov.in एवं पोर्टल http://sppp.raajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।						
DIPRC/10479/2025						
(आर.एन. मंगल) खनि अभियन्ता कोटा						

संघ के वरिष्ठ प्रचारक माणकचंद (भाईजी) पंचतत्व में विलीन

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक माणकचंद के निधन पर शोक व्यक्त किया

जयपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक एवं पाथेय कण पत्रिका के संरक्षक माणकचंद (भाई जी) का बुधवार को एसएमएस अस्पताल में निधन हो गया। वे 83 वर्ष के थे एवं विगत एक माह से किडनी की बीमारी का इलाज ले रहे थे। बुधवार शाम को

■ राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ समेत अनेक गणमान्य लोगों ने अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए

झालाना मोक्षधाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में माणकचंद्र के छोटे भाई कमल चरखा समेत अनेक गणमान्य बंधु शामिल हुए। इससे पूर्व पाथेय भवन में उनकी देह अंतिम दर्शन के लिए रखी गई, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और उद्योग मंत्री राज्यवर्धनसिंह राठौड़ समेत अनेक गणमान्य लोगों ने अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उनके निधन से चर्चा परिवार, पाथेय परिवार एवं राष्ट्रवादी पत्रकारिता जगत को अपूरणीय क्षित हुई है। उनका तपस्वी जीवन और कार्यों की प्रेरणा सदैव स्मरणीय रहेगी। स्थित प्रज्ञ थे, जीया तपस्वी जीवनः माणकचंद ने अपना सम्पूर्ण जीवन संघ कार्य को समर्पित करते



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्व. माणकचंद की पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा शोकाकुल परिजनों को ढांडस बंधाया।

हुए प्रचारक जीवन की कठिन साधना की। माणकचंद का जन्म 2 नवम्बर 1942 को नागौर जिले के कसारी-बड़ा गांव में हुआ था। 1966 में वे पूर्णकालिक प्रचारक बने और छह दशक तक राजस्थान सहित विभिन्न स्थानों पर संगठनात्मक, बौद्धिक एवं वैचारिक कार्य में संलग्न रहे। वे पाथेय कण पत्रिका के प्रबंध संपादक के रूप में 34 वर्षों तक सक्रिय रहे। उन्होंने 1989 से पाथेय कण में प्रबंध संपादक की भूमिका निभाई और वैचारिक पत्रकारिता को नई दिशा दी। उनके संपादकीय नेतृत्व में यह पत्रिका भारतीय विचारधारा की मुखर और प्रतिष्ठित आवाज बनी। आपातकाल के कालखंड में उन्होंने जेल यात्रा भी की और वैचारिक प्रतिबद्धता से कभी

विवर्जित नहीं हुए। संघ के प्रति उनका समर्पण, अनुशासन, संयम, सादगी और संतुलित दृष्टिकोण ने नई पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत है। पाथेय कण के माध्यम से उन्होंने राष्ट्र निर्माण हेतु वैचारिक चेतना का दीप प्रज्वलित किया, जो दीर्घकाल तक स्मरणीय रहेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्व. माणकचंद की पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी: शर्मा ने स्व. माणकचंद की पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा शोकाकुल परिजनों को ढांडस बंधाया। उन्होंने ईश्वर से पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देने एवं शोकाकुल परिवार को यह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने स्व. माणकचंद के व्यक्तित्व को याद

कर कहा कि उनका जीवन उच्च आदर्शों और सिद्धांतों के लिए समर्पित था। समाज में राष्ट्रीय चेतना और मूल्यों के प्रसार में उनके अतुलनीय योगदान को सदैव याद किया जाएगा। पाथेय कण के संरक्षक माणकचंद के निधन पर देवनानी ने गहरा शोक व्यक्त किया। देवनानी ने माणकचंद की पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी: विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पाथेय कण के संरक्षक माणकचंद के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। माणकचंद के निधन का समाचार सुने ही देवनानी एसएमएस अस्पताल पहुंचे। देवनानी ने अस्पताल में माणकचंद की पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

रुडी का राजनीतिक अनुभव बनाम बालियान की क्षेत्रीय पकड़

जयपुर/नई दिल्ली। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सचिव (प्रशासन) के लिए होने वाला आगामी चुनाव राजनीतिक हलकों और मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि इस प्रतिष्ठित पद के लिए मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के दो वरिष्ठ नेताओं के बीच है। एक ओर हैं श्री राजीव प्रताप रूडी जो सात बार के सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और क्लब की कार्यकारी व्यवस्था में दो दशकों से सक्रिय नेतृत्वकर्ता, जिनकी प्रशासनिक दक्षता और समावेशी दृष्टिकोण को व्यापक रूप से सराहा गया है। दूसरी ओर हैं श्री संजीव बालियान, पश्चिम उत्तर प्रदेश से आने वाले पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री,

- भाजपा के दो नेता आमने सामने, रुडी को मिल रहा सर्वदलीय समर्थन
- फ्रेंडली मुकाबले की आड़ में तीखी टक्कर, क्लब चुनाव बना चर्चा का केंद्र

जो क्षेत्रीय सांसदों और विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के समर्थन से मैदान में हैं। हालांकि दोनों ही पक्ष सरकार से समर्थन मिलने का दावा कर रहे हैं, लेकिन भाजपा की ओर से किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। पार्टी ने इसे फ्रेंडली मुकाबले के रूप में सांसदों के विवेक पर छोड़ दिया है।हाल ही में संसद में हुए ऑपरेशन सिंदूर पर रात्रिकालीन चर्चा के दौरान

एक दिलचस्प दृश्य देखने को मिला। बताया जाता है कि जब सदन में सांसद मौजूद थे, तो गृह मंत्री अमित शाह ने मुस्कुराते हुए श्री रूडी से पूछा कि इतनी रात को भी वोट मांग रहे हैं? और फिर स्वाभाविक जिज्ञासा से यह भी पूछा कि कैसा चल रहा है? राजनीतिक हलकों में इस प्रसंग को अधोषिप्त समर्थन के संकेत के रूप में देखा जा रहा है, हालांकि इसकी कोई औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है।

विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस पर पोस्टर का विमोचन

जयपुर। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कहा है कि मानव तस्करी एक गंभीर विषय है और सरकार ने इसे रोकने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। शर्मा बुधवार को पुलिस मुख्यालय में विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस के अवसर पर बच्चों की सुरक्षा विषय पर सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर के सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन द्वारा आयोजित पोस्टर विमोचन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर शर्मा ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों में भी मानव तस्करी एवं महिला तथा बाल सुरक्षा विषय के महत्वपूर्ण प्रावधान रखे गए हैं।

जमीनों को फर्जी दस्तावेज से बेचने वाली गैंग के दो भूमाफिया गिरफ्तार

जयपुर। बजाज नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारत सरकार की ओर से जन्म जमीनों को सेबी के फर्जी दस्तावेज से बेचने वाली जालसाज गैंग के दो भूमाफियाओं को गिरफ्तार किया है और साथ ही कर फर्जी दस्तावेज व

सील मोहरे बरामद की है। इस गिरोह में दिल्ली-हरियाणा के सदस्य भी शामिल हैं, जिनकी तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही है। पुलिस उपयुक्त जयपुर (पूर्व) संजीव नैन ने बताया कि बजाज नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए

भारत सरकार की ओर से जन्म जमीनों को सेबी के फर्जी दस्तावेज से बेचने वाली जालसाज गैंग के आरोपित भेमी कुमार तातेड (49) निवासी बिलाडा जिला जोधपुर और श्रवण रणवा उर्फ सुरेश रणवा (40) निवासी लोसल

सीकर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपित भूमाफिया प्रमोद कुमार तातेड (39) को पुलिस ने पकड़ा। पूछताछ में उसने सरकारी जमीन को सेबी के फर्जी दस्तावेज से सौदा कर बेचना स्वीकार किया।

ग्रेटर निगम में चहते ठेकेदारों को मिले टैंडर, अन्य के ठेके निरस्त

-कार्यालय संवाददाता- जयपुर। ग्रेटर नगर निगम में चहते ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ अफसर खुली दरियादिली दिखा रहे हैं। चुनिंदा ठेकेदारों को तो टैंडर के कार्यादेश तो दिए जा रहे हैं, जबकि अन्य फर्मों के ठेके निरस्त किए जा रहे हैं। हालांकि अब कमिश्नर डॉ. गौरव सैनी ने विवादित सभी टैंडर निरस्त करने की बात कही है। ज्ञात रहे कि पिछले दिनों हेरिटेज सिटी कॉन्टेन्टर्स सोसायटी के अध्यक्ष रघुवीर शर्मा और अन्य ठेकेदारों ने आयुक्त से मुलाकात करके इस मामले की लिखित और मौखिक शिकायत की थी। सूत्रों के मुताबिक ग्रेटर नगर निगम के विद्याधर नगर जोन में पिछले दिनों नाला सफाई और नाला निर्माण के कार्य के करीब 80 से 85 लाख रुपये के दो टैंडर हुए थे, जिसमें करीब 5 प्रतिशत कम रेट पर मैसर्स श्री विल्डर्स और अन्य फर्म को कार्यादेश अधिषापी अधिवंता विविध बड़ाया ने जारी किया था। जबकि विद्याधर नगर जोन में ही इसी तरह के नाला सफाई और नाला

- अधीक्षण अभियंता नितिन शर्मा पर भेदभाव का आरोप लगा रहे ठेकेदार
- ठेकेदार द्वारा ज्यादा रेट डाली गई थी, वह उंची दर पर कार्यादेश का दबाव बना रहा था, इसलिए टैंडर निरस्त किए गए: नितिन शर्मा

निर्माण व मरम्मत के अन्य करीब 4 से 5 टैंडर, जो कि मैसर्स कृष्णा बिल्डर्स एंड कॉन्टेन्टर्स को मिले थे, उन्हें रद्द कर दिया गया। ठेकेदार अनिल अग्रवाल का आरोप है कि अधीक्षण अभियंता नितिन शर्मा ने जानबूझकर ठेके रद्द किए हैं, जबकि इन टैंडर्स में तय रेट से करीब 10 से 15 प्रतिशत दर कम डाली गई थी। जो कि प्रायः प्रत्येक टैंडर में सामान्यतः आती है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जिन टैंडरों में ग्रेटर नगर निगम का राजस्व का फायदा हो रहा था और रेट भी कम आई थी, उन्हें अधिकारियों ने निरस्त क्यों किया? जब ठेका फर्म ने इसकी शिकायत हेरिटेज सिटी कॉन्टेन्टर्स सोसायटी से की तो अध्यक्ष रघुवीर शर्मा के नेतृत्व में ठेकेदारों ने आयुक्त डॉ. गौरव सैनी

से मुलाकात की। रघुवीर शर्मा ने आरोप लगाया है कि ग्रेटर नगर निगम में अधीक्षण अभियंता नितिन शर्मा इन दिनों अपनी मनमानी पर उतरे हुए हैं। वे किसी चहते ठेकेदार को टैंडर देने के लिए कभी तो किसी निविदा को 5 प्रतिशत कम रेट पर भी खोलकर कार्यादेश संबंधित अधिशाषी अभियंताओं से दिलावा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ 10 से 20 प्रतिशत कम रेट के वाले टैंडर्स को निरस्त किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नगरीय निकायों में अधीक्षण अभियंता के पास निकायानुसार 50 लाख रुपए से ऊपर के कार्यों से संबंधित पत्रावलियां भेजी जाती है, परन्तु ग्रेटर नगर निगम में इसके विपरीत छोटी से छोटी फाइलें अधीक्षण अभियंता नितिन शर्मा अपने पास मंगवा

रहे है। चाहे फिर वह 1 लाख रुपये की हो या फिर 50 लाख रुपये की। जबकि राज्य सरकार ने 8 जनवरी 2015 को आदेश जारी कर एस.ओ. पी. बनायी थी। जिसमें प्रत्येक अधिकारी की वित्तीय निर्णय की क्षमता तय की गई थी। इस मामले में अधिशाषी अभियंता नितिन शर्मा का कहना है कि ठेकेदार द्वारा ज्यादा रेट डाली गई थी, वह उंची दर पर कार्यादेश का दबाव बना रहा था, इसलिए टैंडर निरस्त किए गए हैं। जहां तक बात फाइलें मंगवाने की है तो उच्चाधिकारियों के निर्देश पर किसी फाइल को जांच के लिए जरूर मंगवाया गया होगा, परंतु प्रत्येक फाइल हमारे पास नहीं आती। यह हास्यास्पद भी है कि कोई एक अधिकारी ही पूरी फाइलें अपने पास मंगवाए। इस प्रकरण में आयुक्त डॉ. गौरव सैनी का कहना है कि जिन टैंडर्स में ज्यादा दर आयी थी, उन्हें निरस्त किया गया है। जहां तक विद्याधर नगर जोन में 5 प्रतिशत कम रेट पर कार्यादेश दिए जाने की बात है तो उस विवादित टैंडर को भी हम निरस्त करने की कार्यवाही कर रहे हैं।

‘युवाओं में लोकतंत्र की बेहतर समझ बढ़ाने की पहल’

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने और समाधान खोजने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने हेतु शनिवार को राजस्थान विधान सभा में प्रातः 10 बजे से एक दिवसीय युवा संसद होगी। युवा संसद में जयपुर शहर के विद्यालयों के विद्यार्थी, संसद अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हुये राजस्थान विधानसभा के सदन में संसदीय प्रक्रियाओं पर वाद-विवाद करेंगे। देवनानी ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी राष्ट्र की दिशा तय करने वाली शक्ति है। उन्हें यदि लोकतंत्र और संसदीय प्रक्रिया की सही समझ मिले, तो वे समाज के सजग प्रहरी बन सकते हैं। युवा संसद इसी दिशा में एक प्रयास है, जिससे छात्र-छात्राएँ केवल शिक्षा तक सीमित न रहकर समाज और व्यवस्था को गहराई से समझ सकें।



दिन भर बारिश का दौर जारी रहा कभी तेज तो कभी फुहार। सावन के महीने में बारिश की झड़ी लगी रहने से सूरज भी नहीं निकला। सहर के लगभग सभी इलाके में सड़के दरिया बन गई , रेलवे स्टेसन अंडर पास व खाशा कोठी पर भरा बारिश का पानी।

1936 विद्यालयों में मरम्मत के लिए 160 करोड़ रुपये की स्वीकृति

जयपुर। झालावाड़ के पीपलोट स्कूल हादसे के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बहुत पीड़ा का अनुभव किया है। उन्होंने परिवार के मुखिया का कर्तव्य निभाते हुए शोक की इस घड़ी में त्वरित फैसले लेकर ठोस कदम उठाए हैं जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति न हो। गत 25 जुलाई को हुए इस हादसे के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला कलेक्टर की बैठक ली, उन्हें सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए और उसी दिन शाम को साढ़े 6 बजे प्रदेश के 3,688 आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट जारी किया। प्रदेश के 1,936 विद्यालयों में मरम्मत, उन्नयन और विकास कार्यों के लिए 160 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए गए हैं। मेवात, डांग, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम और विधायक कोष से भी मरम्मत के लिए राशि को 15 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया है। हर विधानसभा क्षेत्र में सरकारी कार्यालयों की मरम्मत के

- हादसे के दिन ही 3688 आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट जारी किया

लिए 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि सीएम शर्मा के निर्देशन में शासन और प्रशासन ने इस दुर्घटना के बाद बहुत स्विफ्ट रैस्पोंस दिया। यह दिखाता है कि संकट में हम बस एक हैं और प्रत्येक संकट, खारे को चुनौती के रूप में लेकर जीवटता के साथ इसका जवाब देना हम राजस्थानियों के जीस में है। इसमें नेतृत्व सबसे अभावशाली भूमिका निभाता है और यहां भजनलाल शर्मा ने दिखाया है कि नेतृत्व अथॉरिटी, आदेश देने से कहीं आगे की भूमिका में हैं और वह है, आमजन के साथ तादात्म्य कर उनकी आंकाक्षा, चिंता और आशा को शासन की आंकाक्षा, चिंता और आशा का रूप लेकर लक्ष्य को समय पर प्राप्त करें।

मुंबई साइबर क्राइम के नाम पर 80 लाख की ठगी



सोवन मंडल

जयपुर। साइबर ठगों ने अपनी शांति चालीं से अजमेर की बयासी वर्षीय एक बुजुर्ग महिला को निशाना बनाया और डिजिटल ऑरेंट का डर दिखाकर उनसे अस्सी लाख की भारी भरकम राशि ऐंट ली। इस हाई-प्रोफाइल मामले में राजस्थान साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने मुख्य खाताधारक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बैंक खाते में ठगी की गई सारी रकम ट्रांसफर की गई थी। पुलिस अधीक्षक (साइबर क्राइम) शांतनु कुमार सिंह ने बताया कि यह

घटना 23 नवंबर से 30 नवंबर 2024 के बीच हुई। ठगों ने व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए महिला से संपर्क साधा और खुद को मुंबई साइबर क्राइम का अधिकारी बताया। उन्होंने महिला को डिजिटल रूप से गिरफ्तार होने का झांसा दिया और कानून की कार्रवाई से बचने के नाम पर उनसे अस्सी लाख अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करवा लिए। प्रकरण अजमेर में दर्ज होने के बाद इसे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन राजस्थान, जयपुर को हस्तांतरित कर दिया गया। जिसके बाद जांच में तेजी आई। साइबर थाने की विशेष टीम ने ठगी गई राशि के लेनदेन का गहन विश्लेषण किया। जांच में पाया गया कि ठगी की गई पूरी अस्सी लाख की राशि एक ही बैंक खाते में स्थानांतरित की गई थी। यह खाता सोवन मंडल पुत्र संतोष (30) निवासी धूलिया हावड़ा पश्चिम बंगाल का था। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सोवन मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। उससे आगे की पूछताछ जारी है।

पांच सदस्यीय कमेटी डेयरी बूथ आवंटन पॉलिसी में करेगी संशोधन

जयपुर। राजस्थान में सरस की डेयरी बूथ आवंटन को लेकर पॉलिसी में आवश्यक संशोधन किया जाएगा। इसके लिए पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। इस संबंध में शासन सचिवालय में बुधवार को पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के केबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत की

- बैठक में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत व अन्य अधिकारियों ने बुथ आवंटन नीति-2021 में संशोधन के सुझाव दिए

अध्यक्षता में डेयरी सेवाओं के विस्तार एवं बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। पांच सदस्यीय कमेटी में पशुपालन, डेयरी एवं गोपालन विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा, डीएलबी के डायरेक्टर जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर, नगर निगम आयुक्त डॉ. गौरव सैनी, आरसीडीएफ एमडी श्रुति भारद्वाज, दुग्ध संघ, जयपुर के एमडी मनीष फौजदार को शामिल किया गया है। यह कमेटी बैठक में आए सुझावों के आधार पर प्रस्ताव तैयार करेगी। बैठक में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत व



केबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत(बांये) ने डेयरी सेवाओं के विस्तार एवं बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से बैठक ली।

अन्य अधिकारियों ने बुथ आवंटन नीति-2021 में संशोधन के सुझाव दिए। इनमें बुथ आवंटन हेतु आवेदन पत्र संबंधित जिला दुग्ध संघ में जमा कराने, नए डेयरी बूथों के स्थान आकलन, डेयरी आरसीडीएफ/जिला दुग्ध संघ द्वारा गठित समिति द्वारा चिन्हित कर अंतिम सूचि जारी करने का सुझाव दिया गया। इसके अलावा प्रस्तावित डेयरी बूथ के लिए उसी क्षेत्र के पांच किमी. की परिधि के स्थानीय निवासी को प्राथमिकता देने, सेवारत सेना के जवान के परिवारिक सदस्य को आवेदन के लिए पात्र मानने संबंधी प्रस्ताव को नई नीति में शामिल करने का सुझाव दिया गया। नए सरस पालर खोलने की

संभावनाएं तलाशेगा आरसीडीएफ बैठक के दौरान प्रदेश में नए सरस पालर खोलने के लिए आरसीडीएफ को संभावनाएं तलाशने के लिए निर्देशित किया गया। इसके लिए सरकारी चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज, शैक्षणिक संस्थाओं, बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन के आसपास के क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर सरस पालर खोलने को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि नए सरस पालर खोलने से न केवल आरसीडीएफ की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की

मंशानुसार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ही बजट घोषणा 2024-25 के तहत प्रदेशभर में 2500 नए सरस बुथ खोले जा रहे हैं। इसके तहत 2000 बुथों के लिए कुल 11536 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से जांच के बाद 7861 आवेदन पत्र आरसीडीएफ द्वारा अनुमोदित कर संबंधित निकायों को प्रेषित किए गए हैं। इसके अलावा विगत वर्षों के पैडिंग 500 बुथों का निस्तारण स्थानीय निकाय स्तर पर लंबित है। इस प्रकार कुल 8361 लंबित आवेदन पत्रों का जल्द से जल्द निस्तारण कर लांटेरी के जरिए कुल 2500 बुथों के आवंटन के लिए पांच सदस्यीय कमेटी गठित की गई है।

‘अधिकारी बाढ़ संभावित इलाको को सूचिबद्ध कर कार्मिक नियुक्त करें’

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में हो रही निरंतर बारिश के चलते अधिकारी अलर्ट मोड पर रहें। अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ काम करते हुए राहत एवं सेवागत सेना के जवान के परिवारिक सदस्य को आवेदन के लिए पात्र मानने संबंधी प्रस्ताव को नई नीति में शामिल करने का सुझाव दिया गया। नए सरस पालर खोलने की

है। ऐसे में अधिकारी इनके जल स्तर संबंधी अपडेट लेते हुए निचले और बाढ़ संभावित इलाकों को सूचिबद्ध कर कार्मिक नियुक्त करें तथा उन क्षेत्रों की विशेष निगरानी रखें। उन्होंने कहा कि ऐसे क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार चेतावनी बोर्ड लगाकर किसी भी तरह की दुर्घटना से रोका जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस और होमगार्ड्स के दल पर्याप्त संसाधनों के साथ अलर्ट रहें तथा आमजन को आवाजही को ऐसे स्थानों पर निषेध किया जाए। साथ ही, रा्ट जैसे स्थानों पर पानी चलने के दौरान अस्थायी चौकी

लगाकर वाहनों का आवागमन रोका जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नागरिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रशासन पूरी सक्रियता से काम करे। शर्मा ने प्रदेशवासियों से अपील की कि बारिश के मौसम में विशेष सावधानी बरतें। भारी बारिश, आकाशीय बिजली एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए भी पूरी तरह सतर्क रहें। बाढ़ग्रस्त मार्गों, पुलों और तेज बहाव वाले नदी-नालों को पर कर करने से बचें। साथ ही, प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन करें। किसी भी तरह की आपदा की स्थिति में तुरंत कंट्रोल रूम को जानकारी दें जिससे राहत कार्यों में तेजी

आ सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग द्वारा राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर 1070 तथा 112 एवं जिला स्तरीय हेल्पलाइन नंबर 1077 का 24x7 संचालन कराई जा रहा है। अधिकारी कंट्रोल रूम में आई शिकायतों पर त्वरित एक्शन लेते हुए आमजन को शीघ्र राहत पहुंचाएं। उन्होंने अधिकारियों को अतिवृष्टि से प्रभावित आमजन और पशुधन को सुरक्षित जगहों पर स्थानांतरित करने तथा वहां साफ पानी के साथ नियमित सफाई भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता और सेवाओं को सुचारु रखा जाए।

मुख्यमंत्री ने वर्षा पीड़ित जयपुर शहर की स्थिति का निरीक्षण किया

उन्होंने सांगानेर थाने से मालपुरा गेट तक बनने वाली एलीवेटेड रोड की प्रगति जानी

■ मुख्यमंत्री भजनलाल ने बी-टू बाईपास, सांगानेर, सुमेर नगर, सूरजमल सर्किल, मुहाना मंडी, चौरडिया पेट्रोल पंप आदि स्थानों पर रूक कर जल भराव, क्षतिग्रस्त सड़कों, गड्ढों व ड्रेनेज सिस्टम की समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए।

जयपुर, 30 जुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार शाम को जयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों का लगभग छह घण्टे सघन निरीक्षण कर बारिश से उत्पन्न स्थितियों का जायजा लिया। उन्होंने बी-टू बाईपास रोड, सांगानेर, सुमेर नगर, सूरजमल सर्किल, मुहाना मंडी, चौरडिया पेट्रोल पंप पर रुककर जलभराव, क्षतिग्रस्त सड़कों, गड्ढों एवं ड्रेनेज सिस्टम से संबंधित समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।

शर्मा ने बी-टू बाईपास रोड के पास ड्रव्यवती नदी का अवलोकन किया और घने वृक्षों की छंटाई तथा नालों के फेरो कवर की मरम्मत करने



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार शाम को जयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों का सघन निरीक्षण किया और बारिश से उत्पन्न स्थितियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आमजन से भी फीडबैक लिया।

के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने कच्ची बस्तों के लोगों एवं बच्चों से बातचीत की और अधिकारियों को निचले क्षेत्रों में जल निकासी तथा आपात स्थिति में वहां के निवासियों के लिए भोजन व पेयजल की व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने सांगानेर स्थित कैम्प कार्यालय में लोगों से मुलाकात की और शहर के जलभराव वाले स्थानों के संबंध में जानकारी ली। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मुहाना मंडी चौराहे पर

पहुंचकर जायजा लिया और अधिकारियों को चौराहे पर सर्कल निर्माण के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने महाराजा सूरजमल सर्किल व केसर नगर चौराहे पर क्षतिग्रस्त सड़कों के शीघ्र मरम्मत कार्यों के निर्देश दिए। शर्मा ने निरीक्षण के दौरान सांगानेर क्षेत्र के विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने चौरडिया पेट्रोल पंप तिराहे पर रुककर सांगानेर थाने से चौरडिया पेट्रोल पंप और मालपुरा गेट तक बनने

वाली एलिवेटेड रोड की प्रगति की जानकारी ली तथा संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आमजन से भी फीडबैक लिया। साथ ही, उन्होंने चाय की दुकान पर रुककर चाय भी पी। इस दौरान जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर नगर निगम ग्रेटर सहित, ऊर्जा, सार्वजनिक निर्माण, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

अमेरिका ने बुधवार को भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया

ट्रंप ने रूस से सैन्य उपकरण व तेल खरीदने के कारण भारत पर जुर्माना लगाने की भी बात कही

वॉशिंगटन, 30 जुलाई। लंबे समय से जारी अनिश्चितता पर विराम लगाते हुये, अमेरिका ने बुधवार को भारत पर 25 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने की घोषणा कर दी और रूस से सैन्य उपकरण तथा तेल खरीदने पर जुर्माना लगाने की बात भी कही।

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विथ सोशल पर लिखा कि भारतीय उत्पादों पर पहली अगस्त से 25 प्रतिशत आयात शुल्क लागू हो जायेगा। उन्होंने भारत को "मित्र" बताते हुये कहा कि पिछले कुछ वर्षों में तुलनात्मक रूप से दोनों देशों के बीच कारोबार कम रहा है। इसका कारण भारत का उच्च आयात शुल्क है, जो दुनिया में सर्वाधिक आयात शुल्क लगाने वाले देशों में शामिल है। उन्होंने कहा कि किसी दूसरे देश के मुकाबले भारत में गैर-मौद्रिक बाधायें भी सबसे ज्यादा हैं।

उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि भारत भारी मात्रा में रूस से सैन्य उपकरण खरीदता है। ऐसे समय में, जब सभी चाहते हैं कि रूस "यूक्रेन में हथियारों" रोक दे, भारत चीन के साथ रूस का सबसे बड़ा ऊर्जा खरीददार है। उन्होंने लिखा कि उसका रूस से ऐसा व्यापार करना गलत है और घोषणा की कि पहली अगस्त से भारत 25 फीसदी आयात शुल्क भरेगा। साथ ही रूस के साथ व्यापार करने की एवज में जुर्माना भी भरेगा। अमेरिका ने

■ ट्रंप ने कहा कि भारत -अमेरिका में कारोबार कम होने का कारण भारत का उच्च आयात शुल्क है।

इस साल अप्रैल में भारत पर 26 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने की घोषणा की थी। हालाँकि बाद में भारत समेत सभी देशों के लिए आयात शुल्क के क्रियान्वयन को टाल दिया गया था। भारत के लिए इसे पहले इसकी तारीख नौ जुलाई तय की गयी थी। इस बीच दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत के कारण आयात शुल्क की घोषणा टलती रही। इसके बाद अमेरिका ने जब जापान और यूरोपीय संघ के साथ समझौते के तहत उन पर 15 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने की घोषणा की तो उम्मीद की जा रही थी कि भारत के लिए भी करीब 15 प्रतिशत की दर ही होगी। भारत पर आयात शुल्क और जुर्माने की घोषणा के लिए पहली अगस्त की समय सीमा मतलब पहली अगस्त की समय सीमा – यह सख्त है और इसे बढ़ा या नहीं जायेगा। अमेरिका के लिए बड़ा दिन।" उन्होंने लिखा कि पहली अगस्त अमेरिका के लिए बड़ा दिन होगा।

राज्य उपभोक्ता

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
आदेश की पालना में पुलिस ने यूपी निवासी आरोपी सक्सेना को गिरफ्तार कर आयोग में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मामले से जुड़े अधिवक्ता लोकेश शर्मा ने बताया कि आरोपी संजय सक्सेना सहित, अन्य के खिलाफ आयोग के अध्यक्ष जस्टिस देवेन्द्र कच्छवाह ने गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्देश दिया था।

वहीं, वारंट की पालना पुलिस आनुकूलिक को करने के लिए कहा था। इस आदेश की पालना में ही पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी की। परिवारियों ने सहारा प्राइम सिटी, यानी सहारा सिटी होमस में 2004 में आवासीय इकाइयों खरीदी थीं, लेकिन प्रोजेक्ट तय समय में पूरा नहीं हुआ और उसका कब्जा तय समय, 2012 तक नहीं दिया गया।

मामला आयोग में आने पर परिवारियों के पक्ष में फैसला हुआ। इसके बावजूद, विपक्षी ने आदेश की पालना नहीं की। इस पर परिवारियों ने आयोग में अवमानना याचिका दायर कर आदेश की पालना करवाने का आग्रह किया था।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
अपॉइंटमेंट्स को रोकना जा रहा है। उसी दिन शाम 4:30 बजे हुई दूसरी बैठक में नड्डा और रिजिजू गैरहाज़िर रहे। उसी के बाद अदालत इस्तीफे की खबर आई।

धनखड़ के आवास पर रहे गए विजिटर्स रजिस्टर में यह दर्ज है कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे, महासचिव जयराम रमेश और महाधिवजय सिंह जैसे नेताओं की अक्सर मेजबानी की। जब चंद्रबाबू नायडू ने मोदी को आगह किया, तब नड्डा से कहा गया कि वे धनखड़ को सावधान करें। उन्हें यह भी बता दिया गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा को हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा में महाधिवजय के जरिए नहीं होगी। इस बीच, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के निवास पर एक बैठक हुई, जिसमें लोकसभा में महाधिवजय के लिए 145 सांसदों का हस्ताक्षर जुटाने का प्रयास हुआ। धनखड़ उस समय तक 50 सांसदों के न्यूनतम हस्ताक्षर भी नहीं जुटा पाए थे, जो राज्यसभा में प्रस्ताव लाने के लिए जरूरी

थे। इसलिए घोषणा की गई कि महाधिवजय प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपा गया है, और वे ही आवश्यक प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। यह भी बताया गया कि राज्यसभा में अब तक कोई प्रस्ताव दाखिल नहीं हुआ है, इसलिए लोकसभा के 145 सांसदों का प्रस्ताव ही मान्य होगा। हालांकि, लोकसभा में न्यूनतम 100 हस्ताक्षर पर्याप्त होते हैं। इस घटनाक्रम के साथ ही, धनखड़ की वह योजना विफल हो

और वर्तमान स्थिति पर भी सरकार ने कोई जानकारी नहीं दी या फिर उसके पास कोई जानकारी नहीं थी। इससे सरकार की तैयारी और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठे।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई प्रमुख सवालों के जवाब देने में असफल रही, जैसे आतंकवादी पहलुगाम में घुसे

गई, जिसमें वे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, एक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद की नियुक्ति अपनी पसंद से करना चाहते थे। अब यह अधिकार स्वमेव लोकसभा अध्यक्ष की चला गया है। सरकार नहीं चाहती थी कि विपक्ष राज्यसभा में विपक्षी सांसदों द्वारा लाया गया महाधिवजय प्रस्ताव पारित हो, क्योंकि वह यह दिखाना चाहती थी कि भ्रष्टाचार को लेकर वह खुद सख्त है और वो ही यह प्रस्ताव लाई है।

विपक्ष का मानना है, दो दिन की बहस के बाद भी ऑपरेशन ...

कैसे और हमले के बाद कहाँ चले गए? क्या वे मारे गए, या अब भी फरार हैं? विपक्ष ने सरकार द्वारा तीन आतंकियों के मारे जाने के दावे पर भी सवाल उठाया। विपक्ष ने पूछा कि भारत ने कितने लड़ाकू विमान इस संघर्ष में खोए? ट्रम्प की कथित मध्यस्थता के बाद हमला रोकने से भारत को क्या रणनीतिक लाभ मिला? इसके अलावा, विपक्ष ने इस संकट के दौरान चीन और

ऑपरेशन सिंदूर केन्द्र सरकार की इच्छाशक्ति को दर्शाता है- नड्डा

नयी दिल्ली, 30 जुलाई। राज्य सभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि देश में 2014 के पहले कई आतंकवादी हमले हुए, जिनमें सैकड़ों लोग मारे गये, लेकिन 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद, जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष देश में आतंकवादी घटनाओं पर रोक लग गयी।

उन्होंने कहा कि देश में फौज और पुलिस तो वही होती है लेकिन सरकार के काम करने का तरीका उसकी राजनीतिक इच्छाशक्ति से परिलक्षित होता है। उन्होंने कहा कि 2016 में उरी में जैश-ए-

■ राज्यसभा में सदन के नेता जे पी नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष भारत में आतंकवादी घटनाओं पर रोक लग गई।

मोहम्मद ने आतंकवादी हमला किया था तो प्रधानमंत्री मोदी ने कोशिकोड में कहा था कि उरी हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जायेगा। इसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक से उस हमले का जवाब दिया गया, जिसे सारी दुनिया ने देखा। केन्द्रीय मंत्री ने पहलुगाम आतंकवादी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी ने बिहार के मधुबनी में एक जनसभा में कहा था कि पाकिस्तान ने बड़ी गलती कर दी है और उसे कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। इसी के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अनुबंध- नवीनीकरण करते हुए उसे 20 अगस्त 2026 तक बढ़ा दिया गया। इसी बीच उसे बिना कोई नोटिस और सुनवाई का मौका दिए, 16 जून

किसी भी दुर्घटना में जनहानि की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जायेगी- मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि एक विशेष कमेटी गत 6 वर्ष में बने भवनों की गुणवत्ता जाँचेंगी

जयपुर, 30 जुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सभी विभाग क्षतिग्रस्त, जीर्ण-क्षीर्ण भवनों की तुरंत मरम्मत कराएं, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि अब ऐसी किसी भी दुर्घटना में हुई जनहानि पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गत 6 वर्षों में बने सरकारी भवनों, स्कूलों, आंगनबाड़ियों की सूची बनाएं तथा एक विशेष राज्य स्तरीय कमेटी बनाकर निर्माण गुणवत्ता की जांच की जाए।

शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित बैठक में अधिकारियों को जर्जर भवनों के संबंध में विशेष दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत के लिए आपदा प्रबंधन मद से स्वीकृत प्राप्त की जाए तथा समय पर

■ अधिकारियों की बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों की मरम्मत और रख रखाव पर विशेष ध्यान दिया जाये तथा उनका अनिवार्य निरीक्षण किया जाये।

प्रस्ताव तैयार करके कार्य प्रारंभ किया जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए भवनों के निरीक्षण, मरम्मत और रखरखाव पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। सरकारी कार्यालयों में कार्यरत कर्मिक की अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जर्जर भवनों की जानकारी संबंधित

अधिकारियों को देना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों की मरम्मत और रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा इनका अनिवार्य निरीक्षण किया जाए। बैठक में बताया गया कि जीर्ण-क्षीर्ण एवं क्षतिग्रस्त आंगनबाड़ियों को अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है। शर्मा ने सार्वजनिक निर्माण विभाग, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि सभी सरकारी कार्यालयों, विशेष रूप से स्कूलों, अस्पतालों सहित अन्य सार्वजनिक भवनों का तत्काल निरीक्षण कर पूरी जानकारी के साथ जिलेवार रिपोर्ट बनाएं तथा मरम्मत कार्य करवाए जाएं। बैठक में मुख्य सचिव सुधांशु पंत सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

अन्नपूर्णा रसोई का अनुबंध निरस्त ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
में अनुबंध के तहत ईदिरा रसोई संख्या 329 , नगर, डींग को संचालित करने का काम दिया गया। रसोई संचालन का यह काम उसे तीन साल के लिए दिया था। यह अवधि पूरी होने के बाद याचिकाकर्ता का अनुबंध- नवीनीकरण करते हुए उसे 20 अगस्त 2026 तक बढ़ा दिया गया। इसी बीच उसे बिना कोई नोटिस और सुनवाई का मौका दिए, 16 जून

2025 को उसका अनुबंध बिना किसी कारण तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि राज्य सरकार ने एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए उसका अनुबंध निरस्त किया है। ऐसे में राज्य सरकार के इस आदेश को रद्द किया जाए। याचिका पर सुनवाई करते हुए एकलपिठ ने अनुबंध निरस्त करने के आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार को आतंकवाद, उग्रवाद व नक्सलवाद कांग्रेस से विरासत में मिले

लाल नेहरू समझ जाते तो पाकिस्तान बनता ही नहीं।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने जैसे ही जवाब देना शुरू किया कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने इसका विरोध करते हुए सदन से बहिर्गमन किया। वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से चर्चा का जवाब देने की मांग कर रहे थे। मोदी उस समय सदन में मौजूद नहीं थे।

शह ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म होने के कगार पर है। जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों और द ांचागत परिवर्तनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र स्थापित हो रहा है और वहां पिछले छह

■ केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा राज्यसभा में चर्चा का जवाब शुरू करते ही विपक्षी दलों ने वॉकआउट किया। वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से चर्चा का जवाब मांग रहे थे।

महीने में एक भी स्थानीय युवक की आतंकवादी संघटनों में शामिल हुई है। शह ने कहा कि मोदी सरकार को कांग्रेस की सरकार से आतंकवाद ,

उग्रवाद और नक्सलवाद विरासत में मिले थे। उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर बात करने वाली कांग्रेस को इस आंकड़े पर नजर डालनी चाहिए कि उसके राज में 54 आतंकवादी हमलों में 600 से अधिक लोग मारे गये। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारत ने आत्मरक्षा के सिद्धांत के तहत ऑपरेशन सिंदूर चलाया और आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के भारत के अधिकार का सभी देशों ने समर्थन दिया है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता निंदबन्धम ने उनके इस्तीफे की मांग के साथ प्रश्न उठाया कि पहलुगाम में हमला करने वाले आतंकवादी पाकिस्तानी थे

इसका सबूत क्या है। उन्होंने सवाल किया कि निंदबन्धम किस को बचाना चाहते थे, पाकिस्तान को या आतंकवादियों को। उन्होंने कहा कि यह भी संयोग है कि उन्होंने जिस दिन सवाल पूछा उसी दिन तीनों आतंकवादी ढेर हो गये।

शह ने कहा कि छह मई की रात आतंकवादियों के नौ ठिकानों को निशाना बनाकर 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया गया। यह कार्रवाई आत्मरक्षा के सिद्धांत के तहत की गयी। विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए शह ने कहा कि किसी के कहने पर सैन्य कार्रवाई नहीं रोकी गयी यह पाकिस्तान के अनुरोध पर रोकी गयी।

शह ने कहा कि यह पहला मौका है जब सेनाओं ने पाकिस्तान की सरकार पर हमला कर अपना शौर्य दिखाया है। इससे पहले उसकी कार्रवाई पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर तक ही सीमित रहती थी।

सुप्रीम कोर्ट ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
का दुरुपयोग कर पुष्ट डी की नौकरियों के बदले अपने परिजनों के नाम पर ज़मीन लिखवाई।

सीबीआई का आरोप है कि ये नियुक्तियों बिना किसी विज्ञापन या सार्वजनिक चयन प्रक्रिया के की गई थीं और इसमें पश्चिम मध्य रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका थी, जिन्हें रेल

मंत्री के रूप में लालू प्रसाद के सीधे निर्देश मिले थे। ये नियुक्तियाँ भारतीय रेल की मानक सर्ती प्रक्रिया के खिलाफ पाई गई। जांच के बाद, सीबीआई ने 7 जून को चार्जशीट दाखिल की, जिसमें लालू प्रसाद, उनके परिजनों और 77 अन्य, जिनमें 38 नौकरी पाने वाले उम्मीदवार भी शामिल हैं, को आरोपी बनाया गया था।

‘नागरिकता सबूत पेश करने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
पत्र में यह भी कहा गया कि “ऐसा लगता है, मानो मतदाता सूची को सुधारने के नाम पर चुनाव प्रक्रिया को समाप्त करने के लिये एएसआईआर पर्याप्त नहीं थी, तभी तो इस विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटैन्सिव रिविजन) को इतनी तेजी से लागू करना, बृथ वेलव ऑफिसर्स (बीएलओ) को असंभव समय सीमा देना और डेटा डिजिटाइज करने के लिए अपर्याप्त संसाधन देना, चुनाव आयोग द्वारा तय की गई प्रक्रिया का उपहास बन कर रह गया है।”

रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया, लगातार...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
के भरोसे पर टिका हुआ नहीं होता है। यह अपना आंतरिक मूल्य रखता है और दुनिया में कहीं भी आसानी से इसे नकदी में बदला जा सकता है। भारत ही नहीं, दुनिया भर के केन्द्रीय बैंक अब सोने की ओर रुख कर रहे हैं। मगर आरबीआई की आक्रामक रणनीति इस बात का संकेत है कि भारत आने वाले खतरों को गंभीरता से ले रहा है: जैसे कि अस्थिर अमेरिकी डॉलर, व्यापार युद्ध, बढ़ती महंगाई, और

भू-राजनीतिक तनाव। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की फिर से टैरिफ लगाने की धमकी हालिया वैश्विक चिंता की एक वजह बनी है। उनके बयानों ने वैश्विक व्यापार व्यवस्था और डॉलर की प्रभावता को लेकर अनिश्चितता पैदा कर दी है। ऐसे माहौल में सोना एक सुरक्षा कवच के साथ-साथ, स्वायत्तता व आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी बन जाता है। यह कदम वैश्विक रश्यां से भी मेल खाता है। ब्रिक्स देश, ब्राजील,

रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, लंबे समय से डॉलर के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। ऐसे में सोना, जो कि एक सार्वभौमिक मूल्य का भंडार रहा है, उनकी योजना में स्वाभाविक रूप से फिट बैठता है। भारत के लिए यह केवल बैलेंस शीट में विविधता लाने का कदम नहीं, बल्कि एक तरह की “रिज़र्व डैमोक्रैसी” भी हो सकती है। इसके घरेलू कारण भी हैं। भारतीय रुपया भले ही तुलनात्मक रूप से स्थिर हो, फिर भी वह तेल कीमतों में उछाल या अचानक पूंजीनिकासी जैसे बाहरी झटकों के प्रति संवेदनशील है। ऐसे में अधिक सोना रखकर आरबीआई अपने लिए सुरक्षा आधार तैयार करता है, एक ऐसी संपत्ति, जो ब्याज दरें, प्रतिबंधों या मुद्रा गिरावट से प्रभावित नहीं होती।

आलोचक यह कह सकते हैं कि सोना ब्याज अर्जित नहीं करता, जबकि सरकारी बॉन्ड ब्याज देते हैं। मगर जब दुनिया आर्थिक संकट में हो, तो स्थिरता, मुनाफे से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आरबीआई के कदम यह दिखते हैं कि वह तत्काल लाभ से ज्यादा दीर्घकालिक

स्थायित्व पर ध्यान दे रहा है। असल में, यह सोना-खरीद अभियान केवल संतुष्टता नहीं है, बल्कि यह डॉलर-प्रधान वित्तीय व्यवस्था में एक मौन अविरास का संकेत भी है। यह इशारा करता है कि भारत, बाकी देशों की तरह, एक कठिन आर्थिक रास्ते के लिए खुद को तैयार कर रहा है। भले ही वैश्विक आर्थिक संकट अभी निकट हो या नहीं, आरबीआई इंतज़ार नहीं कर रहा। वह भारत के भंडार को उस संपत्ति से मजबूत कर रहा है, जिसने हर दौर के संकट को सहा है, वह है सोना।

‘जमानती अपराध ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
केस की सुनवाई पूरी होने में लंबा समय लगने की संभावना है। ऐसे में याचिकाकर्ताओं को जमानत पर रिहा किया जाए। दूसरी ओर, राज्य सरकार की ओर से जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ताओं पर अपराध प्रामाणित है।